राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 223 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, गुरूवार ,04 फरवरी 2021 , मूल्य रु. 1.50

संक्षिप्त समाचार

विदेशी शख्सियतों के ट्वीट पर विदेश मंत्रालय सख्त

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का करीब ढाई महीने से प्रदर्शन जारी है। किसानों की मांग है कि केंद्र तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाएं। हालांकि, किसानों के आंदोलन को विदेशी शख्सियतों का भी समर्थन मिल रहा है। बीते दिनों पॉप सिंगर रेहाना ने भी किसानों आंदोलन के समर्थन में खबर को साझा करते हुए ट्वीट किया था। मामले में विदेश मंत्रालय का बयान सामने आ गया है। विदेश मंत्रालय ने विदेशी टिप्पणियों पर साफ किया है कि भारतीय संसद ने पूर्ण चर्चा एवं बहस के बाद सुधारवादी कृषि कानून पारित किया है।

इंटरनेट बंद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटिशन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। किसानों के प्रदर्शन के कारण दिल्ली के बॉर्डर इलाके में इंटरनेट सेवा बंद किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल लेटर पिटिशन में कहा गया है कि तुरंत इंटरनेट सेवा बहाल की जाए। लेटर पिटिशन में 140 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इंटरनेट को सस्पेंड किया जाना कानून की नजर में गलत है। किसान जहां बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां इंटरनेट सस्पेंड करने का केंद्र सरकार का फैसला अधिकार का दुरुपयोग है।

सबसे तेज गति टीका लगाने वाला देश बना भारत : स्वास्थ्य मंत्रालय

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि 18 दिन के भीतर देश में 40 लाख लोगों को कोविड-19 रोधी टीके लगाए गए हैं और इसके साथ ही भारत सबसे तेज गति से इस आंकड़े तक पहुंचने वाला देश बन गया है। बुधवार सुबह तक देश में 41 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड-19 रोधी टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 रोधी टीके लगाने के मामले में भारत एक फरवरी को दुनिया के शीर्ष पांच देशों की सूची में था। भारत तेज गति से यह टीकाकरण जारी रखेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को अन्य मोर्चों पर भी सफलता मिल रही है।

युवक ने निगली 5 इंच बड़ी नुकीली चाकू

भोपाल । मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जहां एक संजय (32 वर्षीय, बदला हुआ नाम) के पेट से सर्जरी कर 5 इंच का नुकीला चाकू निकाला गया है। बताया जा रहा है कि युवक पिछले डेढ़ साल से लोहा व स्टील से बने सामान को खा जाता था। परिजनों को युवक की इस आदत का पता करीब डेढ़ साल पहले तब चला, जब पेट दर्द होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद सोनोग्राफी में उसके पेट में चम्मच और सेफ्टी पिन दिखी। इसके बाद डॉक्टर्स ने पेट की सर्जरी कर चम्मच व सेफ्टी पिन निकाली थी।

किसान आंदोलन पर सड़क से लेकर संसद तक घमासान

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कृषि कानूनों और किसान आंदोलन पर सड़क से लेकर संसद तक घमासान जारी है। राज्यसभा में आज भी किसानों के मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ। हालांकि कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद को जब इस पर बोलने का मौका मिला तो उन्होंने आजादी से पहले से लेकर वर्तमान में किसानों की स्थिति और आंदोलनों का जिक्र कर मोदी सरकार को खूब सुनाया। राज्यसभा में पीएम मोदी के सामने ही गुलाम नबी आजाद ने राकेश टिकैत के पिता महेंद्र टिकैत के साथ कांग्रेस के टकराव वाली स्थिति का जिक्र किया और कहा कि किसानों के साथ लड़ाई लड़ने का कोई फायदा नहीं। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि किसानों और सरकार के बीच जो गतिरोध बना हुआ है, यह पहली दफा नहीं हुआ है। सैकड़ों सालों से किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता रहा है, संघर्ष करता रहा है, कभी जमीनदारी के खिलाफ, कभी सामंतवाद के खिलाफ लड़ते रहे हैं। मैं कुछ अहम आंदोलनों का जिक्र करना चाहता हूं, जिसमें आखिर में सरकार को अंग्रेजों के जमाने में किसानो के सामने झुकना पड़ा।

उन्होंने कहा कि किसानों की ताकत हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी ताकत है और उनसे लड़ाई कर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। मैं इतिहास के कुछ पन्ने यहां रखता हूं। उन्होंने इस दौरान गांधी जी के सत्याग्रह का भी जिक्र किया। गुलाम नबी आजाद ने राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा किए गए किसान आंदोलन को याद करते हुए कहा कि अक्टूबर 1988 में कांग्रेस पार्टी बोट क्लब में एक रैली करना चाहती थी। उन दिनों उसमें पब्लिक मीटिंग करने की इजाजत थी। उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और मैं संगठन मंत्री, यूपी का प्रभारी और रैली का इंचार्ज था। रैली के लिए पूरे देश से ट्रेनें आने वाली थीं और कई दिनों से उत्तर प्रदेश में महेंद्र टिकैत का आंदोलन चल रहा था। लेकिन जब पेपरों में आया कि बोट क्लब में कांग्रेस की रैली होने वाली है, तभी महेंद्र टिकैत जी ने दिल्ली कूच कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि रैली से एक दिन पहले महेंद्र टिकैत जी 50 हजार लोगों के साथ बिस्तरें, खाट, हुक्के और अनाज लेकर बोट क्लब में बैठे थे। हम चकित रह गए। मैं प्रधानमंत्री जी के पास बैठा था और उन्होंने कहा कि इन सबको निकाला जाए, मगर मैंने कहा कि हमें किसानों के साथ लड़ाई नहीं करनी है। हमने अपना रैली स्थल बदल कर लाल किले में कर दिया। हमने घोषणा नहीं की। जहां ट्रेनें आनी थीं और लोग आने वाले थे, वहां सैकड़ों लोगों को लगा दिया ताकि लोगों को बोट क्लब के बदले लाल किला लाया जा सके। हमने लड़ाई नहीं लड़ी, हम खुद को पीछे कर लिए और नतीजा यह हुआ कि दो-तीन दिन बाद महेंद्र टिकैत जी खुद वापस लौट गए। उन्होंने कहा कि किसान 130 करोड़ लोगों को अन्नदाता हैं। इनके बगैर हम कुछ भी नहीं। इंसान को जिंदा रहने के लिए दो वक्त की रोटी ये किसान ही देते हैं। इनसे हमें क्या लड़ाई लड़नी है। हमें लड़ाई लड़ने के लिए और भी फ्रंट हैं। हमारी सीमा पर पाकिस्तान और चीन दुश्मन के रूप में खड़े हैं। हम मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। हम आपके साथ, पूरा देश साथ है और हमारी पार्टी साथ है। चीन और पाकिस्तान आंख उठाकर भी देखता है तो हम आपके साथ हैं, मगर किसानों के लिए क्या।

कृषि कानून पर चल रहे प्रोपेगेंडा पर अमित शाह का बड़ा बयान, विकास तय करेगा भारत का भविष्य

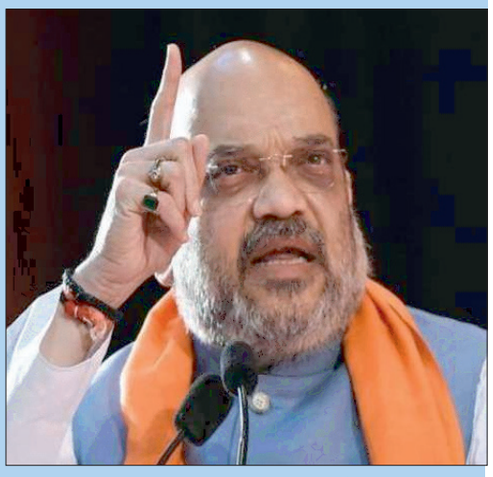

नई दिल्ली, एजेंसी। किसान आंदोलन को लेकर छिड़े घमासान के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के जरिए पलटवार करते हुए कहा कि कोई प्रोपेगेंडा देश की एकता को नहीं तोड़ सकता। एकजुट होकर प्रगति की ओर चलेंगे। कोई भी दुष्प्रचार भारत को ऊंचाइयों तक जाने से नहीं रोक सकता। गृहमंत्री अमित शाह ने ये बातें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के ट्वीट पर लिखी हैं।

ज्ञात हो कि दिल्ली और आसपास चल रहे किसान आंदोलन को लेकर विदेशी हस्तियों ने भी टिप्पणी की है। कृषि कानूनों को लेकर पॉप स्टार रिहाना, पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग, पूर्व एडल्ट स्टार मिया खलीफा और अमेरिकी उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस ने टिप्पणी की है। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। पॉप स्टार रिहाना ने अपने ट्विटर पर किसान आंदोलन पर लिखा था कि हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? वहीं पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग ने कहा था कि हम भारत में किसानों के प्रदर्शन में एकजुटता से खड़े हैं।

बिना जानकारी के कुछ भी कहना गलत

किसानों के मुद्दे पर विदेशी हस्तियों के ट्वीट पर सरकार ने सख्त नाराजगी जताई है। इस मामले में सरकार की ओर से जवाब सामने आया है। विदेशी हस्तियों और संस्थाओं द्वारा हाल की टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ये सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग और कमेंट्स को लेकर प्रलोभन है। इस तरह की टिप्पणियां न तो सटीक और न ही जिम्मेदार हैं। खासकर जब मशहूर हस्तियों और अन्य लोगों द्वारा इसको लेकर बयान सामने आए। सरकार की ओर से कहा गया है कि ऐसी टिप्पणियां करने से पहले सच्चाई जान ली जानी चाहिए और मुद्दों की उचित समझ की जाए। बिना जानकारी के कुछ भी कहना गलत है। भारत की संसद ने पूर्ण बहस और चर्चा के बाद कृषि क्षेत्र से संबंधित सुधारवादी कानून पारित किए हैं।

सरकार के समर्थन में आए अक्षय कुमार और अजय देवगन सहित कई सितारे

रिहाना के ट्वीट के बाद अभिनेता अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अजय देवगन और करण जौहर ने इंडियाटुगेदर हैशटैग के साथ केंद्र सरकार का समर्थन किया है। साथ ही विदेशी हस्तियों द्वारा किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देने को प्रोपेगेंडा बताया है। अभिनेता अक्षय कुमार ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा है कि सरकार किसानों की समस्या का समाधान कर रही है।

दीप सिद्धू, जुगराज सिंह समेत चार लोगों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित

नई दिल्ली, (एजेंसी)। 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर केसरिया झंडा फहराने और उपद्रव को भड़काने के आरोपी अभिनेता दीप सिद्धू अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दीप के गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस लगातार छापामारी कर रही है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू की जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। दीप सिद्धू के अलावा दिल्ली पुलिस ने जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह और गुरजंत सिंह पर भी एक लाख का इनाम रखा है। वहीं, जजबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह की जानकारी देने वाले भी दिल्ली पुलिस ने 50-50 हजार रुपए इनाम देने की घोषणा की है। बता दें कि जिस समय दिल्ली में

दंगे हो रहे थे उस समय दीप सिद्धू लाल किले में ही मौजूद था और भड़काऊ भाषण दे रहा था। लेकिन, हिंसा होते ही वो फरार हो गया। पुलिस ने दीप सिद्धू के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है लेकिन वो है कहा ये अभी तक किसी को नहीं पता है। दीप सिद्धू पर जब पुलिस कमिश्नर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो भी हिंसा में शामिल है उसे बक्शा नहीं जाएगा। दीप सिद्धू पुलिस के हाथ तो नही आ रहा लेकिन 26 जनवरी के बाद वो सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव है। दिल्ली से भागने के बाद दीप सिद्धू की लोकेशन हरियाणा थी उसके बाद उसकी लोकेशन पंजाब हो गई। इसके बाद पुलिस को जानकारी मिली कि वो बिहार में हो सकता है, लेकिन वो पकड़ में नही आया। फिलहाल क्राइम ब्रांच की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी है पुलिस का दावा है कि उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। दीप सिद्धू पंजाबी फिल्मों के अभिनेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी। दीप ने अपने फिल्मी करियर की शुरूआत पंजाबी फिल्म रमता जोगी से की थी, जिसे लेकर कहा जाता है कि इसके निमार्ता धर्मेंद्र हैं।

अभी बिल वापसी की बात है, अगर गद्दी वापसी की बात कर दी...

जींद, (एजेंसी)। हरियाणा के जींद जिले में किसानों की महापंचायत शुरू हो गई, इसमें हजारों की भीड़ जुटी है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी महपंचायत में हिस्सा लेने पहुंची है। महापंचायत में फैसला हुआ कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस ले और गिरफ्तार लोगों को जल्द से जल्द रिहा करे। महापंचायत से राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चुनौती देकर कहा है कि हमारे द्वारा अभी सरकार से बिल वापस की बात कही गई है, अगर गद्दी वापसी की बात कर दी, तब सरकार का क्या होगा। राकेश टिकैत ने सरकार को बेबाक अंदाज में चुनौती दी है। महापंचायत में कृषि बिल को वापस लेने का प्रस्ताव पास किया गया है। महापंचायत में किसानों ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की मांग की है। इसके अलावा लापता किसानों का पता लगाकर किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की गई है। महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि जब-जब राजा डरता है, तब-तब किलेबंदी करता है। दिल्ली में कीलें लगाई जा रही हैं, हम वहां अपने खेतों में भी लगाते हैं। टिकैत ने कहा कि अभी जींद वालों को दिल्ली कूच की जरूरत नहीं है, आप यहां पर ही रहे। टिकैत के अलावा कई खाप नेता भी महापंचायत में शामिल हुए हैं। टेक राम

कंडेला ने कहा कि किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए यह बड़ा जमावड़ा है। करीब दो दशक पहले हरियाणा में किसानों का आंदोलन चलाने वाली कंडेला खाप ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को अपना समर्थन दिया है। दूसरी खाप ने भी आंदोलन का समर्थन किया है। टेकराम कंडेला ने कहा कि आज के कार्यक्रम में कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग की जाएगी। गौरतलब है की जब टिकैत भावुक हुए थे,तब कंडेला गांव के लोगों ने जींद चंडीगढ़ हाईवे जाम कर दिया था, जिसके बाद पूरे हरियाणा भर से किसान आंदोलन को समर्थन मिला था और बड़ी संख्या में लोग दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच गए थे। जींद जिले ने किसान आंदोलन में नए सिरे से जान फूंकी है। आज हरियाणा के जींद में किसान आंदोलन को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। कंडेला प्रधान ने कहा कि 26 जनवरी की हिंसक घटना के बाद जब आंदोलन पर सवालिया निशान खड़े हो गए थे, तब कंडेला गांव के किसानों ने उसी रात हाइवे जाम कर आंदोलन को दोबारा खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी। उसी के बाद अगले दिन 27 जनवरी को प्रदेश के लगभग सभी जगहों पर खाप महापंचायतों ने दिल्ली जाने का फैसला किया। किसान आंदोलन का आज 70वां दिन है, आज भी नए कृषि कानूनों पर तकरार जारी है। जींद के कंडेला गांव में महापंचायत चल रही है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे है।भारी संख्या में मंच पर लोग होने के कारण राकेश टिकैत जिस मंच पर खडे.थे वह टूट गया। इस दौरान राकेश टिकैत बाल-बाल बच गए। बताया जा रहा है कि भीड़ अधिक होने के कारण राकेश टिकैत का मंच टूटा। नए कृषि कानूनों पर बने गतिरोध के चलते राजधानी दिल्ली से लगी गाजीपुर, टीकरी और सिंघु बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन आज 70वें दिन भी जारी है।

सरकार का काम किसानों को मारना-धमकाना नहीं, समस्या का समाधान करना है: राहुल गांधी

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि किसान हिन्दुस्तान की शक्ति है, उसे दबाना, धमकाना, मारना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करके इस समस्या का समाधान करना है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं किसानों को बहुत अच्छे से जानता हूं, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार को ही पीछे हटना होगा। फायदा है सबका कि आज हट जाएं। कांग्रेस ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, दिल्ली किसानों से घिरा हुआ है। दिल्ली को किले में क्यों बदला जा रहा है? हम उन्हें क्यों धमका रहे हैं, मार रहे हैं? सरकार उनसे बात क्यों नहीं कर रही है? इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रही है? यह समस्या देश के लिए अच्छी नहीं है।

राहुल ने आगे कहा, पीएम ने कहा कि दो साल तक इस कानून को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव अभी भी सरकार की मेज पर है। इसका क्या मतलब है? या तो आप मानते हैं कि आपको कानूनों से छुटकारा पाने की आवश्यकता है या नहीं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। सरकार को सुनने की जरूरत है क्योंकि किसान कहीं नहीं जा रहे हैं।

राहुल गांधी ने चीन का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, चीन भारत में प्रवेश करता है और हमारी जमीन पर कब्जा लेता है। आप उन्हें क्या संदेश देते हैं? कि हम अपने रक्षा व्यय में वृद्धि नहीं करेंगे। आपने इसे 3000-4000 करोड़ रुपये बढ़ा दिया। आपने क्या संदेश दिया? आप भारत में प्रवेश कर सकते हैं और जो चाहें कर सकते हैं, हम अपने रक्षा बलों का समर्थन नहीं करेंगे। बजट के बारे में बात करते हुए कहा, मैंने बजट से उम्मीद की थी कि भारत की 99 प्रतिशत आबादी को सरकार सहायता प्रदान करेगी। लेकिन यह बजट 1 प्रतिशत आबादी का है। आपने छोटे और मध्यम उद्योग के लोगों, श्रमिकों, किसानों से पैसे छीन लिए और इसे 5-10 लोगों की जेब में डाल दिया।

वायुसेना की बढ़ेगी ताकत, सरकार ने एचएएल से 48 हजार करोड़ के 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद का सौदा किया

बेंगलुरु । भारतीय वायुसेना को तेजस लड़ाकू विमानों से लैस करने के लिए सरकार ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ बड़ा करार किया है। सरकार ने बुधवार को 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान खरीदने के लिए सरकारी एचएएल के साथ बुधवार को 48 हजार करोड़ रुपये के सौदे पर औपचारिक मुहर लगाई। सरकार ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ हुए इस सौदे को रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा मेक इन इंडिया करार बताया है।

रक्षा मंत्रालय के खरीद मामलों के महानिदेशक वीएल कांता राव ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में एचएएल के प्रबंध निदेशक आर माधवन को यह अनुबंध एयरो इंडिया-2021 के उद्घाटन के अवसर पर सौंपा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा- मैं बहुत खुश हूं। एचएएल को भारतीय वायुसेना से 83 नए स्वदेशी एलसीए तेजस एमके1ए के निर्माण का अनुबंध मिला है। इन विमानों की अनुमानित लागत 48

हजार करोड़ रुपये से अधिक है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि यह आज तक का सबसे बड़ा मेक इन इंडिया रक्षा करार है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया तेजस एक इंजन वाला बेहद कुशल मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। मालूम हो कि हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने एचएएल से 73 तेजस एमके-1ए के साथ साथ 10 एलसीए तेजस एमके-1 ट्रेनी विमान खरीदने पर मुहर लगाई थी।माधवन ने कहा कि 48 हजार करोड़ रुपये के अनुबंध के तहत भारतीय वायुसेना को तेजस एलसीए की आपूर्ति मार्च 2024 से शुरू हो जाएगी। कुल 83 विमानों की आपूर्ति पूरी होने तक सालाना करीब 16 विमानों की आपूर्ति की जाएगी। भारत के अलावा दुनिया के कई दूसरे मुल्कों ने भी तेजस विमान खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। आने वाले एक-दो वर्षों में इन विमानों के निर्यात के ऑर्डर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एचएएल की मानें तो इन 83 एलसीए एमके1ए विमानों का उत्पादन बेंगलुरू की दो इकाइयों में होगा।

माना जा रहा है कि इन विमानों के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा। मालूम हो कि एकल इंजन वाला तेजस न सिर्फ स्वदेश निर्मित है वरन अपने लेवल के अन्य विदेशी विमानों से कई मायनों में बेहतर है। यह बाकी विमानों की तुलना में काफी किफायती भी है। बीते दिनों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आर माधवन ने बताया था कि अगले साल स्वदेशी तेजस बहुद्देशीय लड़ाकू विमान का और लेटेस्ट वर्जन सामने आ सकता है।

सदन में फोन का इस्तेमाल विशेषाधिकार का उल्लंघन, होगी कार्रवाई; राज्यसभा अध्यक्ष ने दी चेतावनी

नई दिल्ली । राज्यसभा अध्यक्ष एम. वेंकैया नायडू ने बुधवार को सदन के सदस्यों को रिकॉर्डिंग के लिए फोन का इस्तेमाल करने पर चेताया। अध्यक्ष ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सदन की कार्यवाही को मोबाइल फोन से रिकार्ड न करें यह सांसदों को मिले विशेष अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने मीडिया हाउसेज को भी इस तरह की रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल ब्रॉडकास्टिंग के लिए करने से बना किया। सदन के अध्यक्ष ने कहा, मोबाइल फोन का इस्तेमाल विशेषाधिकार का उल्लंघन है और मीडिया को भी इस तरह की रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है। अध्यक्ष ने कहा, सदन में फोन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ सदस्य मोबाइल फोन से सदन की कार्यवाही रिकॉर्ड कर रहे हैं। सदस्यों को इस तरह की अनुचित गतिविधियों से दूर रहना चाहिए, सदन की कार्यवाही की इस तरह रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पर इसके प्रसार से विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना हो सकती है। ऐसा व्यवहार संसदीय मर्यादा के खिलाफ है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।दरअसल, मंगलवार को सदन में हुई नारेबाजी को कुछ सदस्यों ने अपने फोन में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। विपक्ष ने मंगलवार को सदन स्थगित करने पर विवश कर दिया था। सोमवार को वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद मंगलवार को जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब विपक्ष की ओर से कृषि कानूनों को लेकर दिए गए सस्पेंशन नोटिस को राज्यसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ।

सोमालियाः मोगादिशु में आत्मघाती हमला, पांच की मौत, अल-शहाब ने ली हमले की जिम्मेदारी

मोगादिशु। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक होटल के बाहर आत्मघाती कार बम विस्फोट में कम से कम पांच लोगों की मारे जाने की सूचना है। इस हमले में कई लोग घायल हैं।

घायलों में कुछ की हालत गंभीर है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को एडेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के समीप एक होटल के बाहर विस्फोटकों से भरी कार में विस्फोट हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी अल-शहाब आतंकी समूह ने लिया है।

इस्राइलः नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने छोड़ी पानी की तेज बौछार

येरुशलम। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने उन पर सर्द मौसम में भी पानी की बौछार छोड़ी। प्रदर्शनकारी हर हफ्ते येरुशलम में

नेतन्याहू के आधिकारिक आवास के बाहर एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हैं और यह सिलसिला सात महीने से भी अधिक समय से चला आ रहा है।

पुलिस की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया कि प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। उसने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव किया, वस्तुएं फेंकी तथा पुलिस अवरोधकों को तोड़ने का प्रयास किया। इसमें एक अधिकारी मामूली रूप से घायल हो गया जिसके बाद कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेतन्याहू पद पर नहीं रह सकते हैं क्योंकि उन पर धोखाधड़ी, विश्वासघात और रिश्वत लेने का मुकदमा चल रहा है। उन्होंने नेतन्याहू पर कोरोना वायरस संकट से ठीक से नहीं निपटने का भी आरोप लगाया है। इस्राइल में 23 मार्च को होने वाले चुनाव के लिहाज से तैयारी की जा रही है।

रूस में विपक्षी नेता नवलनी को रिहा करने की मांग तेज, 2,300 लोगों को किया गया गिरफ्तार

मॉस्को। जेल में बंद विपक्षी नेता एलेक्सी नवालनी की रिहाई की मांग को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों की लहर को बरकरार रखा जिससे रूसी संसद (क्रेमलिन) में हलचल मच गई। इस प्रदर्शनों में 2,300 लोगों के गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी पर नजर रखने वाले समूह ओवीडी-इंफो ने बताया कि अब तक पुलिस ने रूस के 11 टाइम जोन के कई शहरों में आयोजित विरोध प्रदर्शन में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच मॉस्को में अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए।

क्रेमलिन के पास कई मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया और बस यातायात में कटौती की गई। यही नहीं बल्कि रेस्तरां और मॉल को भी बंद रहने का आदेश दिया गया। बता दें कि भ्रष्टाचार विरोधी 44 वर्षीय नवालनी रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े आलोचक हैं जिन्हें 17 जनवरी को जर्मनी से लौटते समय गिरफ्तार कर लिया गया था। जर्मनी में पांच माह उन्होंने नर्व-एजेंट (तेज जहर) के इलाज में लगाए। नर्व-एजेंट देने का आरोप भी पुतिन के समर्थकों पर लगा था। नवालनी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पेरोल के नियमों का पालन नहीं किया है।

चेतावनियों के बावजूद की रैली

रूस की सरकार ने नवालनी समर्थकों को रैली आयोजित नहीं करने को लेकर कई चेतावनियां जारी की थीं लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। मॉस्को प्रशासन का कहना है कि करीब 300 लोग अब तक प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं, जबकि फुटेज से पता चल रहा है कि पुलिस बड़ी संख्या में लोगों को बसों में बिठा रही है। साइबेरियाई शहर नोवोसिबिर्स्क में करीब 2,000 लोगों ने आजादी और पुतिन चोर हैं, के नारे लगाते हुए रैली निकाली। याकुट्स्क में मायनस 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के बावजूद रैली निकाली गई। येकाटेरिनबर्ग में करीब 7,000 लोग रैली में उमड़े जबकि ओमस्क में भी सैकड़ों ने रैली निकाली।

पाकिस्तान की फिर फजीहतः पीआईए की दो दिन में दूसरी एयर होस्टेस कनाडा पहुंचकर लापता, वहां शरण लेने का शक

इस्लामाबाद/टोरंटो। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन कंपनी 'पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस' फिर फजीहत का शिकार हो गई। दो दिन में दूसरी बार ऐसा हुआ जब PIA का कोई कर्मचारी कनाडा पहुंचकर लापता हुआ। इस बार भी होटल से गायब होने वाली कर्मचारी एयर होस्टेस है। माना जा रहा है कि यह कर्मचारी इसलिए लापता हुए हैं क्योंकि वे कनाडा में शरण चाहते हैं।

PIA की हालिया फजीहतों का सिलसिला पिछले साल से शुरू हुआ। सितंबर 2020 में खुद सरकार ने संसद में खुलासा किया कि देश के 40त्र पायलट्स के पास फर्जी डिग्रियां और लाइसेंस हैं। इसके बाद पिछले महीने मलेशिया ने लीज रेंट न चुकाने पर

पैसेंजर्स से भरा प्लेन जब्त कर लिया। अब कनाडा में एयर होस्टेस गायब हुई हैं।

पाकिस्तान नहीं लौटीं जाहिदा

'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' के मुताबिक, घटना रविवार की है। PIA की फ्लाइट नंबर PK-797 कनाडा के शहर टोरंटो पहुंची। इसके क्रू मेंबर्स रिटर्न फ्लाइट के पहले होटल चले गए। लौटते वक्त जाहिदा बलोच नाम की एक एयर होस्टेस फ्लाइट स्टाफ में नहीं थीं। इसके एक दिन पहले ही एक और एयर होस्टेस लापता हुई थी। इसके अलावा रमजान गुल नाम का एक फ्लाइट अटेंडेंट भी कुछ दिन पहले लापता हो गया था।

PIA ने दोनों एयर होस्टेस के लापता होने की पुष्टि की है। एक बयान में एयरलाइंस ने कहा- हमने संबंधित विभाग को इस बारे में जानकारी दी है। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडाई सरकार दोनों एयर होस्टेस का पता लगाने में मदद करेगी।

होटल से गायब PIA की दोनों एयर होस्टेस बाकी क्रू मेंबर्स के साथ होटल पहुंची थीं। इसके बाद जब रिटर्न फ्लाइट के लिए स्टाफ एयरपोर्ट पहुंचा तो एयर होस्टेस लापता थीं। इसके बाद हड़कम्प मच गया क्योंकि यह दो दिन में दूसरा मामला था। इसके पहले भी कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं। माना जा रहा है कि बेहतर जिंदगी और कॅरियर की तलाश में ये एयर होस्टेस लापता हुई हैं। कुछ दिनों बाद वे कानूनी तरीके से कनाडा की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती हैं।

इजराइल के पीएम की मोदी से बातचीत : नेतन्याहू ने अपनी एम्बेसी के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए शुक्रिया कहा

तेल अवीव। 29 जनवरी को नई दिल्ली में इजराइली एम्बेसी के बाहर हुए धमाके की जांच जारी है। इस बीच, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। नेतन्याहू के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बातचीत की जानकारी दी गई है।

नेतन्याहू ने मोदी को इजराइली एम्बेसी के कर्मचारियों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। भारत सरकार ने धमाके के बाद इजराइली एम्बेसी के आसपास सुरक्षा बेहद सख्त कर दी है।

मोसाद जांच में मदद कर रही है

'टाइम्स ऑफ इजराइल' ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि इजराइली खुफिया एजेंसी मोसाद नई दिल्ली में हुए ब्लास्ट केस की जांच में भारतीय जांच एजेंसियों की मदद कर रही है। भारत में इसकी जांच हद्ध और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही हैं। मोसाद की टीम भी जांच में शामिल है। डिप्लोटमैटिक लेवल पर भी दोनों देश इस धमाके की गुत्थी सुलझाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। 29 जनवरी

को हुए धमाके में तीन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। धमाका एम्बेसी से करीब 150 मीटर दूर हुआ था।

सीसीटीवी फुटेज में दिखे थे दो संदिग्धः पुलिस ने घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी से दो संदिग्धों की पहचान की थी। ये लोग एक कैब से उतरते हुए दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने कैब ड्राइवर से पूछताछ कर संदिग्धों का स्केच तैयार कराया था। 29 जनवरी को देर रात कई इलाकों में छापेमारी कर दो लोगों को हिरासत में भी लिया था। हालांकि उनसे मिली जानकारी का ब्यौरा नहीं दिया गया।

टेलीग्राम अकाउंट की पड़तालः इजराइली दूतावास के पास हुए ब्लास्ट को लेकर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल एक टेलीग्राम अकाउंट की पड़ताल कर रही है। इस अकाउंट से ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था। इसमें जैश-उल-हिंद नाम के एक संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

आतंकी हमला ही था

इजराइली दूतावास के पास शुक्रवार को हुए ब्लास्ट को इजराइल के राजदूत रॉन मलका ने आतंकी हमला करार दिया है। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए मलका ने शनिवार को कहा, हमारे पास इस पर भरोसा करने के पर्याप्त कारण हैं कि यह आतंकी हमला था। हम इससे हैरान नहीं है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद पिछले कुछ हफ्तों से हम अलर्ट थे। इजराइल के डिफेंस ने हमले के पीछे ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का हाथ बताया है।

राफेल की खरीद के बाद नजरें जंगी विमान F-vzEX पर, अमेरिका की सरकार से हो रही बात, बोइंग ने दी जानकारी

वाशिंगटन। फ्रांस से राफेल और स्वदेशी तेजस की खरीद के बाद भारत की नजर नई पीढ़ी के दूसरे अत्याधुनिक विमानों की खरीद पर है। इसके संकेत अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग से मिल रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि भारत और अमेरिका की सरकारों के बीच जंगी विमान एफ-15ईएक्स के बारे में बातचीत हुई है। इतना ही नहीं इस सिलसिले में दोनों देशों की वायुसेना के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान किया गया है।

अमेरिका की सरकार ने भारतीय वायुसेना को इस नए बहुउद्देश्यीय जंगी विमान की बिक्री के लिए बोइंग को हरी झंडी दे दी है। बोइंग इंटरनेशन सेल्स ऐंड इंडस्ट्रीयल पार्टनशिप्स की उपाध्यक्ष मारिया एच लैने ने बताया कि भारत को एफ-15ईएक्स विमान देने के हमारे लाइसेंस संबंधी अनुरोध को अमेरिका की सरकार ने स्वीकार कर लिया है। दोनों देशों की सरकारों के बीच चर्चा हुई है। दोनों देशों की वायुसेना ने एफ-15ईएक्स के बारे में सूचनाओं का आदान-प्रदान किया।

रिपोर्ट के मुताबिक एफ-15ईएक्स विमान एफ-15 (स्न15) विमानों की सीरिज का सबसे नया और आधुनिक वर्जन है। यह विमान बहुउद्देश्यीय होने के साथ ही हर मौसम में मार करने में सक्षम है। दिन हो या रात हर समय उड़ान भरने और दुश्मन को निशाना बनाने की कम्बैट क्षमताओं से लैस है। अप्रैल 2019 में भारतीय वायुसेना ने करीब 18 अरब डॉलर की लागत से 114 विमानों के अधिग्रहण के लिए शुरुआती निविदा जारी की थी जिसे हाल के वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य खरीद बताया गया था। बोइंग ने यह भी जानकारी दी कि बेंगलुरू में अगले हफ्ते से शुरू हो रहे एयरो इंडिया 2021 में एफ-15ईएक्स विमान को प्रदर्शित किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की ओर से आयोजित होने जा रहे इस एयर शो अमेरिकी बमवर्षक विमान बी-1बी लांसर भी दर्शकों का रोमांच बढ़ाएगा। यही नहीं 83 एलसीए तेजस मार्क 1ए विमानों का सौदा आगामी एयरो इंडिया शो में किया जाएगा। इन बहुआयामी 114 युद्धक विमानों को भारतीय वायुसेना के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपये में खरीदा जाएगा।सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 83 एलसीए तेजस मार्क 1ए की खरीद के लिए मंजूरी दी है।

पर्ल हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट में पाक सरकार की अपील खारिज, अमेरिका ने लगाई थी फटकार

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पर्ल हत्याकांड के अभियुक्तों को रिहा करने के आदेश को निलंबित करने की सरकार की अपील खारिज कर दी है। अमेरिका के फटकार लगाने के बाद पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में अलकायदा आतंकवादी और उसके तीन साथियों को रिहा करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने हालांकि मुख्य आरोपी अहमद उमर शेख और उसके तीन साथियों फहद नसीम, शेख आदिल और सलमान साकिब की अंतरिम हिरासत को एक दिन के लिए बढ़ा दिया है, जिससे सरकार की इस केस में स्थिति को सुना जा सके। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के अटार्नी जनरल ने पर्ल हत्याकांड के अभियुक्तों को रिहा करने के सिंध हाईकोर्ट के निर्णय को खारिज करने का आग्रह किया था। इससे पहले सिंध प्रांत की सरकार ने चारों

आतंकवादियों को रिहा करने के निर्णय पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।बाद में अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के दबाव के कारण पाकिस्तान के अटार्नी जनरल ने शनिवार को घोषणा की थी कि पाकिस्तान सरकार सुप्रीम कोर्ट में पक्ष बनकर 28 जनवरी के निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील करेगी।

कम्युनिस्ट पार्टी ने देश के नेतृत्व के लिए न्गुएन फू त्रांग को फिर से चुना अपना प्रमुख

वियतनाम। वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी ने न्गुएन फू त्रांग को फिर से अपना प्रमुख चुन लिया है। इसके साथ ही त्रांग देश के सबसे शक्तिशाली नेता बन गए हैं और उनका पांच वर्ष के लिए यह तीसरा कार्यकाल होगा। कोरोना के चलते हनोई में मंगलवार को खत्म होने वाली 13वीं नेशनल पार्टी कांग्रेस के समय को एक दिन कम किया गया और इस वजह से मतदान भी तय अवधि से एक दिन पूर्व कराया गया।

पांच वर्ष के लिए फू त्रांग का तीसरा कार्यकाल होगा, एक दिन पूर्व कराया गया मतदान

वियतनाम एक दलीय कम्युनिस्ट राष्ट्र है, इसलिए पार्टी के नेता लगभग स्वतः ही सरकार का नेतृत्व प्राप्त करते हैं यद्यपि पार्टी निकायों और विधायिका में चर्चा हो सकती है। पार्टी में जमीनी स्तर पर शुरू हुई प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस में 1,587 प्रतिनिधियों का चयन हुआ। 200 सदस्यों वाली केंद्रीय समिति ने त्रांग को महासचिव और 18 सदस्यीय पोलित ब्यूरो का प्रमुख चुना जो पार्टी का शीर्ष निकाय है।

कांग्रेस प्रतिनिधियों ने समिति का निर्वाचन किया जिसने पोलित ब्यूरो की सदस्यता के लिए मतदान किया। मतदान में पोलित ब्यूरो सदस्यों की रैंकिंग तय की जाती है जिससे तय होता है कि शीर्ष चार पद- कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नेशनल असेंबली का अध्यक्ष किसे मिलेंगे। इनमें महासचिव का पद सबसे शक्तिशाली है।

चीनी कार्रवाई के डर से ब्रिटेन पहुंचे हांगकांग के हजारों लोग

लंदन। अचीन द्वारा हांगकांग में लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के चलते हजारों लोग अपना घर छोड़कर ब्रिटेन पहुंचे हैं। इनमें से कुछ को डर है कि लोकतंत्र समर्थकों के प्रदर्शन में साथ देने के कारण उन्हें दंडित किया जा सकता है। कई का मानना है कि उनके जीवन जीने के तरीके और नागरिक आजादी पर चीनी दखल असहनीय हो गया है, इस कारण वे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए विदेश जाकर बसने को मजबूर हुए हैं।

लोकतंत्र के समर्थन में चीन से दंड मिलने व नागरिक आजादी पर मंडरा रहा खतरा

एक जानकारी के मुताबिक, हांगकांग में घरबार छोड़कर ब्रिटेन पहुंचे लोगों में से कई ने यहां कभी वापस नहीं लौटने का मन भी बना लिया है। हांगकांग में व्यवसायी और दो बच्चों की मां सिंडी की इस क्षेत्र में कई संपत्तियां हैं लेकिन वे भी अभिव्यक्ति की आजादी और निष्पक्ष स्वतंत्रता पर बंदिशों को लेकर अब लंदन

जाकर बस गई हैं। इसी तरह ब्रिटेन पहुंची वांग ने अपना पूरा नाम न बताकर कहा कि वे हांगकांग से बहुत जल्द बाहर निकलना चाहती हैं क्योंकि बीजिंग उन्हें बाहर जाने से रोक देगा। दूसरी तरफ, ब्रिटेन ने 'ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज' (बीएनओ) वीजा के लिए रविवार से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस कारण भी लोग पहले से ही यहां के लिए हांगकांग छोड़ चुके हैं। ब्रिटेन ने कहा है कि बीएनओ दर्जे वाले करीब 7,000 लोग यहां पहुंचे हैं।

50 लाख लोगों के लिए ब्रिटेन ने खोले रास्ते

ब्रिटेन ने एलान किया था कि वह हांगकांग के 50 लाख लोगों के लिए विशेष आव्रजन मार्ग खोलेगा, ताकि वे ब्रिटेन में रह सकें, काम कर सकें और अंततः यहां बस सकें। इस बीच, रविवार को हांगकांग के निवासियों के ब्रिटेन आने

कई का मानना है कि उनके जीवन जीने के तरीके और नागरिक आजादी पर चीनी दखल असहनीय हो गया है, इस कारण वे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए विदेश जाकर बसने को मजबूर हुए हैं।

व त्वरित व्यवस्था के जरिये नागरिक बनने के लिए आवेदन करने का एक नया वीजा मार्ग आधिकारिक रूप से खोल दिया गया। उम्मीद है कि हांगकांग के करीब तीन लाख लोग इसके लिए आवेदन करेंगे। यह व्यवस्था ब्रिटिश नागरिक (अप्रवासी) (बीएन-ओ) पासपोर्ट धारकों और उनके आश्रितों के लिए है।

मॉस्कोनेपाल में असली 'कम्युनिस्ट' कौन? प्रचंड के बाद अब ओली करेंगे पांच फरवरी को शक्ति प्रदर्शन

काठमांठू। नेपाल की राजधानी काठमांडो की सड़कों पर खुद को असली कम्युनिस्ट और ज्यादा ताकतवर दिखाने की जंग तेज हो गई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के एकतरफा फैसले के बाद संसद भंग किए जाने से नाराज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पुष्प कमल दहल प्रचंड धड़े ने पहले सड़कों पर शक्तिप्रदर्शन किया, फिर ओली को पार्टी से निकाल दिया। अब ओली अपने समर्थकों के साथ खुद को असली कम्युनिस्ट पार्टी का नेता बताने के लिए पांच फरवरी को शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इससे दो दिन पहले उनके समर्थन में एक मोटरसाइकिल रैली भी निकाली जाएगी। इसके लिए सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की बागमती प्रॉविन्स कमेटी ने नारायणहिति रोड पर ओली के नेतृत्व में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। नारायण हिति पैलेस नेपाल में राजशाही के दौरान सबसे चर्चित रहा है। ये नेपाल नरेश का महल है जो 2006 में राजशाही के खात्मे के दो साल बाद यानी 2008 में संग्रहालय बना दिया गया। यह काठमांडो के बीचोंबीच है और इसे शहर का सबसे प्रतिष्ठित केन्द्र और भीड़भाड़ वाला इलाका माना जाता है। द हिमालयन टाइम्स की खबर के मुताबिक एनसीपी के बागमती प्रॉविन्स कमेटी के सचिव खेम प्रसाद लोहानी बताते हैं कि कार्यक्रम में 13 जिलों के कार्यकर्ता और प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और ताजा राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में आम लोगों को जानकारी देंगे। संसद भंग होने के बाद मई में होने वाले चुनाव के मद्देनजर इस सभा को खासा अहम माना जा रहा है।

अरविंद केजरीवाल सरकार किसान आंदोलन के दौरान लापता हुए लोगों का पता लगाने के लिए किसानों के साथ खड़ी है। सरकार ने आज दिल्ली के विभिन्न जेलों में बंद 115 किसानों की सूची जारी की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मैं जिन लापता लोगों के नाम इस सूची में नहीं है, उनकी तलाश करने का पूरा प्रयास करूंगा और जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से बात करूंगा।

किसान आंदोलन से लोगों का गायब होना चिंताजनक : केजरीवाल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आए कुछ लोगों के लापता होने पर चिंता जताई है। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि धरना स्थलों से किसानों के गायब होने का मुद्दा गंभीर चिंता का विषय है। हम उन्हें उनके परिवारों से मिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीते कुछ दिनों में हमें कई लोगों ने संपर्क कर बताया है कि किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आए किसान वापस घर नहीं लौटे हैं। उनका पता नहीं चल पा रहा है, वह लोग मिसिंग हैं। मैं समझ सकता हूं कि जिन लोगों के घर के लोग वापस नहीं लौटे उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। यह सभी सरकारों का दायित्व है कि जो लोग लापता हैं उन्हें ढूंढकर परिवारों को सूचित करके उनके सुपुर्द किया जाए। बीते कुछ दिनों से किसान संगठन के लोगों ने सरकार से और मुझसे व्यक्तिगत तौर पर संपर्क किया है। कल किसान संगठन के कुछ लोग मुझसे मिलने भी आए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बाद हमने दिल्ली की जिन-जिन जेलों में 26 जनवरी की घटना के बाद से किसान आंदोलन से संबंधित लोग बंद हैं। उनकी एक लिस्ट तैयार करवाई है। ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग जेलों में हों और घर पर संपर्क नहीं कर पाए हों, इसलिए आज हम किसान आंदोलन से संबंधित जो भी लोग जेलों में बंद हैं उनकी सूची जारी कर रहे हैं। इससे परिवार के लोगों को उनके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। ऐसे 115 लोगों की सूची बनाई गई है जो कि दिल्ली की अलग-अलग जेलों में बंद हैं। इन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो लोग मिसिंग है उनके परिवार के लोग यह सूची देख सकते हैं। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि उनके घर के लोग गिरफ्तार तो नहीं हुए है। यदि वे गिरफ्तार हुए हैं तो किस जेल में हैं।अगर उसके बाद भी कुछ लोग मिसिंग रह जाते हैं तो हमने किसान संगठन के लोगों को उन्हें तलाश करने का आश्वासन दिया है। अगर इसके अलावा कोई सूचना मेरे पास आएगी कि लोग मिसिंग है तो उन्हें ढूंढने के लिए प्रयास करूंगा। जरूरत पड़ी तो हम एलजी साहब से मदद लेंगे। इस बारे में केंद्र सरकार से भी बात करेंगे। हम परिवार के लोगों को भी बताना चाहते हैं कि जो लोग भी मिसिंग है उनका पता करके आपको सूचित करेंगे।

सिंघु बॉर्डर पर किसानों के लिए न पानी और न शौचालय की सुविधा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस ने देश की राजधानी में किसानों को आने से रोकने के लिए लगभग हर एंट्री प्वाइंट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने सिंघु बॉर्डर को भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। सिंघु बॉर्डर पर किसानों के लिए पानी और शौचालय तक की सुविधा भी नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदर्शनकारी किसानों को देश की राजधानी में आने से रोकने के लिए दिल्ली-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर दिल्ली पुलिस ने कंक्रीट की 5 फीट चौड़ी दीवार बनाई है। 1.5 किमी के नेशनल हाईवे के क्षेत्र में 5 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। पटियाला के एक किसान कुलजीत सिंह ने कहा कि हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित किए बिना अपने गांवों को वापस नहीं जाएंगे। हम किसान हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम ट्यूबवेल बोर करेंगे। कुलजीत ने कहा कि सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए की उनके डराने से हम डर जाएंगे। किसान कुलजीत ने कहा कि अब यहां कुछ ही टॉयलेट होने के कारण शौचालय की दिक्कत हो रही है। कुछ लोग खुले में जाने को मजबूर हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की साइड कूडे.का ढेर लगा हुआ है और कुछ खाली पड़े भूखंडों में गंदगी भरी हुई है। इससे काफी परेशानी हो रही है। कैथल से बीकेयू के स्वयंसेवक मंजीत ढिल्लों ने कहा कि किसानों को दिल्ली की ओर जाने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं में कटौती करने के लिए किलेबंदी की गई है।

दिल्ली मेट्रो में टोकन का काम करेंगे डेबिट और क्रेडिट कार्ड

नई दिल्ली, (संवाददाता)। दिल्ली मेट्रो में सफर करने के लिए आपका डेबिट, क्रेडिट कार्ड के अलावा आपका स्मार्ट मोबाइल फोन ही आपका टिकट होगा। मेट्रो के सभी 285 मेट्रो स्टेशन पर मोबाइल से क्यूआर कोड या डेबिट क्रेडिट कार्ड स्कैन करके आपको प्रवेश मिल सकेगा। दिल्ली मेट्रो ने सभी तीनों चरणों के नेटवर्क पर ओपन लूप टिकटिंग के लिए निविदा जारी की है। मेट्रो के मुताबिक इससे मेट्रो की खर्चे में कमी आएगी। साथ ही स्टेशन पर व्यस्त समय में स्मार्ट कार्ड व टोकन के लिए लगने वाली लंबी कतार भी खत्म होंगी। मेट्रो ने इच्छुक कंपनियों को क्यूआर कोड, ईएमवी (यूरोपे, वीजा, मास्टरकार्ड) के अलावा रूपे डेबिट, क्रेडिट कार्ड आधारित अकाउंट बेस्ड टिकटिंग के लिए आवेदन मांगें हैं। यह आवेदन सिर्फ किसी एक लाइन या एक चरण के नेटवर्क के लिए नहीं बल्कि तीनों चरणों में अब तक बने 389 किलोमीटर स्टेशन के लिए मांगें गए हैं। वर्तमान में यह सुविधा सिर्फ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर लागू है। हालांकि, वहा पर भी सिर्फ रूपे आधारित डेबिट व क्रेडिट कार्ड उपलब्ध है। मेट्रो निविदा के मुताबिक इच्छुक कंपनियां न सिर्फ टिकटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएंगी। बल्कि, ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम के रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी भी उनकी होगी। नई टिकटिंग व्यवस्था से पैसे सीधे यात्री के अकाउंट से कटेंगे। उसके लिए उन्हें अलग से स्मार्ट कार्ड या टोकन खरीदने की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। यह कब तक लागू होगा यह कंपनियों की ओर से आने वाले प्रस्ताव पर निर्भर करेगा। हालांकि, मेट्रो की कोशिश है कि यह सुविधा इसी साल के भीतर शुरू कर दी जाए।

युवाओं में कौशल एवं उद्यमिता का विकास दिल्ली सरकार की पहली प्राथमिकता : आतिशी

नई दिल्ली, (संवाददाता)। दिल्ली विधानसभा की शिक्षा समिति की अध्यक्ष एवं विधायक आतिशी ने मंगलवार को दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय का दौरा कर शिक्षकों एवं छात्रों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का इरादा एक आला और आकांक्षी विश्वविद्यालय बनाना है, जो शहर के युवाओं को आकर्षित करे। युवाओं को कौशल शिक्षा देना व उनमें उद्यमिता का विकास करना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली कौशल व उद्यमिता विश्वविद्यालय का उद्देश्य ऐसे पाठ्यक्रम की शुरूआत करना है, जो बाजार की मांगों को पूरा कर सके और रोजगार की समस्या को खत्म कर सके। वहीं, विवि की उपकुलपति निहारिका वोहरा ने कहा कि 2021-22 के केंद्रीय बजट में कौशल विकास को महत्व तो दिया गया है, लेकिन भारत जैसे बड़े देश के लिए इस बजट में आवंटित राशि बहुत कम है। दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय सभी ट्रेडों के लिए खुला हैं। विश्वविद्यालय बहुत जल्द ही अपने अग्रिम सत्र में प्रथम बैच की शुरूआत करने जा रहा है, जिसमे नए पाठ्यक्रम शामिल होंगे। दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय की शुरूआत की थी। दिल्ली में विवेक विहार, झंडेवालान, द्वारका, पूसा रोड व रजोकरी में स्किल केंद्र हैं, अब दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्य करेंगे। साथ ही बाकी के 16 विश्वस्तरीय कौशल केंद्र, दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय के विस्तारित कैंपस के रूप में कार्य करेंगे। वहीं, दक्षिणी निगम के स्थायी समिति अध्यक्ष राजदत्त गहलोट की ओर से पेश किए गए संशोधित बजट अनुमान 2020-21 और बजट प्रस्ताव 2021-22 पर सदन में चर्चा शुरू हो गई है। मंगलवार को दक्षिणी निगम की सदन की विशेष बैठक में चर्चा हुई। चर्चा में जहां भाजपा के आठ सदस्यों ने बजट पर अपनी राय रखी तो वहीं आम आदमी पार्टी से दो और कांग्रेस से एक पार्षद ने चर्चा में भाग लिया। बुधवार को दूसरे दिन चर्चा होगी। इसके बाद नेता सदन नरेंद्र चावला 11 फरवरी को विशेष बैठक में बजट पेश करेंगे। इस दौरान सदन जिन प्रस्तावों को स्वीकार कर ले, वहीं प्रस्ताव अगले वित्त वर्ष में लागू होंगे।

नई दिल्ली में बुधवार को दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में पॉवर ओवर लोडिंग की समस्या के समाधान के लिए आज नव निर्मित आधुनिक 66/11 केवी ग्रिड का उदघाटन किया।

हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की मांग वाली जनहित याचिका खारिज

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा के सिलसिले में 26 जनवरी को या उसके बाद सिंघु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर के पास अवैध रूप से हिरासत में लिए गए किसानों समेत सभी लोगों को रिहा करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी। याचिका में कहा गया था कि 26 जनवरी को राजधानी में ट्रैक्टर परेड के दौरान भड़की हिंसा के बाद करीब 200 लोग लापता हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और पुलिस को गणतंत्र दिवस पर राजधानी में हुई हिंसा के सिलसिले में दर्ज एफआईआर में कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने गणतंत्र दिवस पर हुए प्रदर्शनों के सिलसिले में 26 जनवरी से पुलिस द्वारा कथित तौर पर अवैध हिरासत में लिए गए लोगों को फौरन रिहा करने का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज करते हुए यह निर्देश जारी किया। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए यह भी कहा कि यह प्रचार पाने के उद्देश्य से दायर की गई याचिका प्रतीत होती है। विधि स्नातक याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उन्हें खबरों और सामाजिक कार्यकताओं के जरिये यह पता चला है कि लोगों को सिंघु, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर से हिरासत में लिया गया है। हरमन प्रीत सिंह ने अपनी याचिका में दावा किया था कि दिल्ली पुलिस ने 27 जनवरी को कहा था कि उसने राजधानी में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के सिलसिले में 200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है और अब तक 22 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। यह याचिका वकील अशिमा मंडला और मंदाकिनी सिंह के जरिये दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने 26 जनवरी की घटनाओं के बाद लापता हुए और हिरासत में लिए गए 15 लोगों के नाम भी दिए थे। याचिका में दलील दी गई कि इस तरह की हिरासत का समर्थन करने के लिए कानूनी रूप से कोई ठोस कारण नहीं है। गौरतलब है कि केंद्र के नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के समर्थन में 26 जनवरी को किसान संगठनों की ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनों ने दिल्ली में हिंसक रूप धारण कर लिया था। साथ ही, कई प्रदर्शनकारी लाल किले में प्रवेश कर गए थे और इस ऐतिहासिक स्मारक की प्राचीर पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया था।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आठ अधिकारियों का तबादला किया

नई दिल्ली, (संवाददाता)। किसान आंदोलन और ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं का असर दिल्ली पुलिस पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जी हां, पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने आठ अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। कुछ को जिले व अन्य महत्वपूर्ण पदों से हटाया गया है तो कुछ को बेहद अहम जिम्मेदारी भी सौंपी गई हैं। इन अधिकारियों में डीसीपी (पुलिस मुख्यालय) चिन्मय बिस्वाल का नाम भी शामिल है, जिन्हें अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में महत्वपूर्ण पद दिया गया है। 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी बिस्वाल को साउथ ईस्ट जिले के बाद पुलिस मुख्यालय की जिम्मेदारी दी गई थी, अब वह डीसीपी क्राइम होंगे। 12 मार्च 2020 को आईपीएस अधिकारी चिन्मय बिस्वाल को पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) के रूप में तैनात किया गया था। दिल्ली पुलिस के आठ अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। आदेश के मुताबिक पश्चिम जिले की कमान संभालने वाले डीसीपी दीपक पुरोहित को पदोन्नति मिली है। उन्हें अब एडिशनल सीपी के रूप में पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। उनके स्थान पर उर्विजा गोयल अब डीसीपी वेस्ट दिल्ली होंगी। वहीं बाहरी उत्तरी जिले के इलाके में सिंघु बॉर्डर की निगरानी करने वाले डीसीपी गौरव शर्मा को जिले से हटाकर डीसीपी (सुरक्षा) के पद पर ट्रांसफर कर दिया गया है। उनकी जगह अरुणाचल प्रदेश से आए राजीव रंजन सिंह को डीसीपी आउटर उत्तरी जिला बनाया गया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से ही आई ईशा पांडेय अब डीसीपी-पीसीआर होंगी।

आगे बढ़ना है तो विज्ञान विषय पर देना होगा ध्यान, छावनी परिषद के स्कूल में बोलीं मीनाक्षी लेखी

पश्चिमी दिल्ली । भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली छावनी में सदर बाजार स्थित अलंकार सामुदायिक भवन, गोपीनाथ बाजार स्थित डा. एपीजे अब्दुल कलाम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व उरी एंक्लेव स्थित मदर टेरेसा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बनकर तैयार दो-दो मंजिला नई इमारत का उद्घाटन किया। इस दौरान छावनी परिषद की उपाध्यक्ष रचना कादियान, पार्षद प्रियंका चौधरी, कविता जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसवीआर चंद्रशेखर, कार्यपालक अभियंता अल्केश शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे।

मीनाक्षी लेखी ने छावनी परिषद के कार्यों को सराहते हुए कहा कि जनता की सुविधा अनुसार यदि कोई परियोजना बनाई जाती है तो सही मायनों में वहीं अच्छा नेतृत्व है। उन्होंने कहा कि अब तक सुविधा के अभाव के कारण छावनी में बच्चे दसवीं के बाद साइंस विषय में पढ़ाई नहीं कर पाते थे।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बात करें तो उनमें भी साइंस लैब की सुविधा नहीं है बल्कि बहुत कम ऐसे स्कूल है जहां साइंस विषय को पढ़ाया जाता है।

किसी भी देश को आगे बढ़ना है या किसी भी देश से प्रतियोगिता करनी है तो उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, गणित व इलेक्ट्रिकल ये तीन विषय काफी महत्वपूर्ण है। ये विषय प्रगति की ओर बढ़ाने का रास्ता है। हमे इन विषयों पर ध्यान देना होगा और बच्चों को छोटी सी उम्र से अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी।

छावनी परिषद ने अच्छी शुरुआत की है। उम्मीद है यहां छावनी परिषद के बच्चों को अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा और आने वाली पीढ़ियां विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की करेगी। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छे अध्यापकों का चयन कर वैदिक गणित की वर्कशाप को छावनी स्कूलों में शुरू किया जा सकता है।

इसके अलावा संस्कृत को आधार बनाकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ज्ञान बच्चों को दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम भूल जाते है कि हमारे देश की सभ्यता व संस्कृति केवल पौराणिक इतिहास नहीं है।

किसानों की चेतावनी के बाद पुलिस अलर्ट, सड़कों पर कील की चादर और 10 लेयर की सुरक्षा

नई दिल्ली । केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन करीब दो महीने से ज्े यादा से जारी है। छह फरवरी को किसान संगठनों द्वारा नेशनल और स्टेट हाईवे को जाम किया जाएगा। किसान संगठन भारतीय किसान मोर्चा (आर) के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि शनिवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक नेशनल और स्टेट हाईवेज को पूरी तरह ठप किया जाएगा। किसानों की चेतावनी के बाद पुलिस अलर्ट है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इधर, किसान दिल्े ली के तीनों बॉर्डर पर जमे हुए हैं। सिंघु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की काफी संख्े या जमा है। किसानों की मांग है कि जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

टीकरी बार्डर पर सड़क पर कील की परत

किसानों की 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के समय जो हिंसा हुई, उससे सबक लेते हुए अब टीकरी बार्डर पर सुरक्षा की लेयर लगातार बढ़ाई जा रही हैं। लोहे के बैरिकेड के अलावा जर्सी बैरियर की दोहरी लेयर और सड़क पर कील की परत बिछा देने के बाद सीमेंट और सरिये से नई दीवार बनाई जा रही है।

मंगलवार को दिन भर यहां पर पुलिस की ओर से ये इंतजाम किए जाते रहे। यहां पर सुरक्षा बल भी बढ़ाया गया है। दिल्ली पुलिस की टुकड़ी भी तैनात है। इस तरह के प्रबंध किए गए हैं कि 100 मीटर के दायरे में ही सुरक्षा की 10 लेयर बनाई गई है। पुलिस बल के अलावा सीमा सुरक्षा बल, रैपिड एक्शन फोर्स, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। 24 घंटे यहां पर पूरा सुरक्षा अमला अलर्ट मोड पर रहता है।

सबसे पहले किसानों के पंडाल के पास बैरिकेडिंग है। यह किसानों ने ही कर रखी है। इससे आगे दिल्ली पुलिस की ओर से पहले लोहे के बैरिकेड की दोहरी लेयर, फिर सीमेंट के बैरियर की दोहरी लेयर, इससे आगे सामान्य बैरिकेड हैं। इनके बीच में भारी सुरक्षा बल तैनात है। इससे बाद करीब तीन-तीन फीट के हिस्से में सड़क के दोनों किनारों तक सरिये से बनी कील बिछाई गई है। यहां से आगे अब सीमेंट के बैरियर लगाकर उनके बीच सरिये और सीमेंट-कंकरीट भर दिया गया है। ताकि यह एक मजबूत दीवार बनी रही। इससे आगे फिर बैरिकेडिंग है। वहां पर सुरक्षा बल तैनात हैं।

इसके बाद से जिग-जैग अंदाज में कंटेनर, पुराने, ट्राले, सीमेंट के बड़े-बड़े बैरियर रखे गए हैं। पुलिस व सुरक्षा बल का अमला शिफ्टों में यहां पर मुस्तैदी दिखा रहा है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा को लेकर 26 जनवरी को जो हुआ, उसके बाद किसानों की बात का विश्वास नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं अब बहादुरगढ़ में भी आंदोलन स्थल पर चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है। इसके अलावा डिजिटल तरीके से भी प्रशासन ने निगरानी करने का निर्णय लिया है। इसके लिए टीकरी बार्डर से लेकर सेक्टर नौ बाईपास तक आंदोलन स्थल पर पीटीजेड (पैन टिल्ट जूम स्टाइल) सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है। पुलिस विभाग ने उपायुक्त से आंदोलन स्थल पर पीटीजेड सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है। बहुत जल्द ही यह सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगा दिए जाएंगे। क्या होता है पीटीजेड कैमरा पैन टिल्ट जूम स्टाइल के कैमरे सर्विलांस के वक्त दाएं-बाएं तो घुमाए ही जा सकते हैं, साथ ही इन्हें मनचाहे ऑब्जेक्ट पर जूम भी किया जा सकता है।

सिंघु बार्डर पर सुरक्षा व्यवस्था हुई और कड़ी, NH-1 से धरना स्थल तक पहुंचना हुआ मुश्किल

नई दिल्ली/सोनीपत/गाजियाबाद । तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में सिंघु बॉर्डर पर चल रहा धरना-प्रदर्शन बुधवार को 70वें दिन में प्रवेश कर गया। सिंघु बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक से लेकर सिंघु बॉर्डर यानी धरना स्थल तक आम नागरिकों के साथ साथ पत्रकारों का प्रवेश भी बंद है। इस बीच हरियाणा के जींद जिले में हुई महापंचायत में राकेश टिकैत ने कई बड़ा एलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को तीनों केंद्रीय कृषि बिलों को रद करना ही पड़ेगा। बताया जा रहा है कि जींद से लौटने के बाद राकेश टिकैत यूपी बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरना-प्रदर्शन की कमान संभाल लेंगे।

टीकरी बार्डर पर नुकीले कील की पट्टी बिछाने के अब कंक्रीट के ढांचे पर प्लास्टिक का जाल लगाने की तैयारी चल रही है। पुलिसकर्मियों का कहना है यदि आंदोलनकारियों ने इस ओर पत्थरबाजी की तो जाल के कारण पुलिसकर्मी बचे रहेंगे।

हरियाणा के जींद जिले के कंडेला गांव में आयोजित किसान महापंचायत में मंच टूटने से भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के राष्ट्रीय प्रवक्े ता राकेश टिकैत और अन्े य किसान गिर गए। मंच टूटने के बाद राकेश टिकैत और पंजाब के किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल सहित कई नेता मंच के साथ नीचे गिर गए। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं लगी। बड़ी संख्े या में लोगों के मंच पर चढ़ जाने के कारण यह टूटा।

मंडी हाउस पर लाल किला और दिल्ली हिंसा के गुनाहगारों को रिहा करने की मांग को लेकर वाम संगठनों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये लोग मंडी हाउस से संसद तक कूच करने की तैयारी में हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन या मार्च को गलत ठहराया है और यहां से जगह खाली करने की लगातार अपील कर रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मार्च को देखते हुए मंडी हाउस और संसद भवन जंतर-मंतर जाने वाले सभी रास्तों को बैरिकेड से बंद कर दिया गया, इस कारण जाम की समस्या भी हो रही है। कई वाहन रास्ते में फंसे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की की नौबत बन रही है। पुलिस इन लोगों के पीछे ढकेल रही है, जबकि ये लोग बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। वहीं, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन सहित आसपास के लोकेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई दी गई है। यहां तक कि धारा-144 भी लागू कर दी गई है।

आगामी 6 फरवरी को देशभर में होने वाले चक्का जाम को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि वह दिल्ली-एनसीआर में चक्का जाम नहीं करेंगे। साथ ही 6 फरवरी के चक्के जाम को लेकर राकेश टिकैत ने बयान दिया कि दिल्ली-एनसीआर के पास ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि किसान अपनी-अपनी जगहों पर सड़क बंद करेंगे और प्रशासन को ज्ञापन भी देंगे।

इस बीच दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को लाल किला हिंसा में आरोपित दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजंत सिंह, गुरजंत सिंह, जगबीर सिंह, बुटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह पर इनाम घोषित किया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एलान किया है कि वह बुधवार को जींद में कंडेला गांव पहुंच रहे हैं। वह यहां किसानों के लिए होने वाली महापंचायत में हिस्सा भी लेंगे। बता दें कि जींद में हो रही इस महापंचायत में हरियाणा के करीब 50 खापों के प्रतिनिधि भी महापंचायत शामिल होंगे। इस महापंचायत में किसान आंदोलन की आगामी रणनीति बनाई जाएगी।

सिंघु के साथ टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर मिलाकर हजारों की संख्या में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आए किसान तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल पर सवार करीब 300 उपद्रवियों ने लाल किला के अंदर जमकर उत्पात मचाया था। उपद्रवियों के आते ही लाल किले का लाहौरी गेट बंद कर दिया गया था।

अक्टूबर तक चलेगी आंदोलन - राकेश टिकैत- इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि यह आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा, इसके बाद इस पर बैठक कर फैसला लिया जाएगा।

संपादकीय

शेयरों में उछाल से मामूली सुकून

कोरोना महमारी की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट से क्या हम तेजी से उबरने लगे हैं? गुरुवार को बंबई शेयर सूचकांक आश्चर्यजनक रूप से 50 हजार के आंकड़े के पार चला गया। अपने 145 साल के इतिहास में पहली बार बीएसई ने इस ऊंचाई को छुआ है। दूसरी तरफ, रिजर्व बैंक का मानना है कि देश की जीडीपी दर सकारात्मक होने के करीब है, और वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में यह बढ़कर 0.1 फीसदी हो सकती है। सरकार यह भी मान रही है कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 7.7 फीसदी की ही गिरावट हो सकती है, जो पहले 10 फीसदी आंकी गई थी। जाहिर है, ये आंकड़े किसी को भी सुकून दे सकते हैं। मगर इन्हीं आंकड़ों के आधार पर पूरी अर्थव्यवस्था को सेहतमंद बता देना भ्रम पैदा करने जैसा होगा। सबसे पहले बात शेयर बाजार की। यह लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। अपने यहां अब भी महज तीन फीसदी आबादी इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाती है। इसकी तुलना यदि अमेरिका जैसे देश से करें, तो वहां शेयर बाजार में लगभग आधी आबादी निवेश करती है। दिक्कत यह भी है कि अपने यहां 0.1 फीसदी कारोबारी ही पूरे शेयर बाजार पर हावी हैं। ये वे लोग हैं, जिनकी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। जैसे कि तकनीक और प्रौद्योगिकी से जुड़ी कंपनियां, एफएमसीजी यानी उपभोक्ता वस्तु बनाने वाली कंपनियां आदि। इसीलिए शेयर बाजार की इस उछाल को आम लोगों की आर्थिक तरक्की से नहीं जोड़ सकते। सेंसेक्स की इस तेजी की एक वजह और भी है। अब बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों में ब्याज कम हो गए हैं। इनमें ब्याज दरें लगातार घटती गई हैं, जिसके कारण निवेशक नए विकल्प तलाश रहे हैं। रियल एस्टेट उनके निवेश का एक रास्ता जरूर था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसमें भी मंदी छाई हुई है। अच्छी बात है कि कोरोना संकट को देखते हुए अमेरिका, यूरोप जैसे देशों के बाजार में वहां के केंद्रीय बैंकों ने तरलता बढ़ाई है। अपने यहां भी नौ लाख करोड़ रुपये की नकदी बाजार में आने की बात कही जा रही है। चूंकि बैंकों की हालत अभी खस्ता है और रियल एस्टेट से आमद कम, इसलिए स्वाभाविक ही शेयर बाजार की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है।

जनवरी 2020 की तुलना में भी हमारी अर्थव्यवस्था अब भी लगभग 10 फीसदी कम है। लॉकडाउन हटने के बाद कुछ ही कंपनियां खुद को संभाल सकी हैं। विमानन उद्योग, पर्यटन उद्योग, होटल-रेस्तरां आदि की हालत तो अब भी खस्ता है। आकलन यह है कि ऐसी स्थिति अभी एक-डेढ़ साल तक बनी रहेगी। इसका सीधा मतलब है कि इतने दिनों तक बाजार में भी अनिश्चितता बनी रहेगी। उम्मीद जरूर कोरोना टीकाकरण अभियान से है, और माना जा रहा है कि जैसे-जैसे इसमें गति आती जाएगी, अर्थव्यवस्था में सुधार दिखने लगेंगे। मगर टीकाकरण की रफ्तार को देखकर यही कहा जा सकता है कि देश की 60 फीसदी आबादी को टीका लगने में एक साल का वक्त लग जाएगा। यानी बाजार अभी अनिश्चितता में फंसा रहेगा। ऐसे में, शेयर बाजार की यह तेजी इसलिए भी छलावा साबित हो सकती है, क्योंकि अब भी यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि कोविड-19 संक्रमण की नई लहर अपने यहां नहीं आएगी। कई देशों में कोरोना संक्रमण बढ़ने पर फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। इसलिए जब तक हम 'हर्ड इम्यूनिटी' विकसित नहीं कर लेते, बाजार के स्थिर होने का दावा नहीं कर सकते। अपने यहां साल 2007 के दिसंबर में सेंसेक्स पहली बार 21 हजार के पार गया था। उस वक्त दुनिया भर में जबर्दस्त तेजी थी। मगर सब-प्राइम संकट की वजह से जब अमेरिका में प्रॉपर्टी बाजार का गुब्बार फूटा, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डूब गई। हर देश के शेयर बाजार 50 फीसदी से भी ज्यादा गिर गए। अपने यहां भी तब सूचकांक घटकर 9,000 पर आ गया था। 1990 के दशक के हर्षद मेहता घोटाले ने भी आम लोगों की जमा-पूंजी को डूबा दिया था। इसीलिए शेयर बाजार को असल अर्थव्यवस्था से अलग माना जाता है। रही बात सकल घरेलू उत्पाद की, तो इसके तिमाही आंकड़े लगातार अच्छी तस्वीर दिखा रहे हैं। यह वाजिब भी है। हमने अब अपने बाजार पूरी तरह से खोल दिए हैं। लॉकडाउन के दौरान देशव्यापी बंदी की जो स्थिति थी, वह अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। ऐसे में, उत्पादन का बढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक है, जिसका असर बाजार पर भी दिख रहा है और आंकड़ों में भी। मगर सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में मुख्यतः संगठित क्षेत्र को शामिल किया जाता है। इसमें कृषि को छोड़कर किसी असंगठित क्षेत्र की गिनती नहीं होती। हमारी अर्थव्यवस्था में 14 फीसदी हिस्सा कृषि का है, जबकि 31 प्रतिशत के करीब हिस्सेदारी गैर-कृषि असंगठित क्षेत्र की है। वित्तीय संस्थाएं यह मान बैठती हैं कि संगठित क्षेत्र की तरक्की के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र भी समान गति से आगे बढ़ते हैं। वास्तव में, यह सोच गलत है।

यदि असंगठित क्षेत्र को भी जीडीपी के आंकड़ों में शामिल कर लें, तो अब भी हमारी अर्थव्यवस्था नकारात्मक 10 फीसदी होगी और उसकी सालाना गिरावट निगेटिव 29 फीसदी। यह भी इस आधार पर अंदाजा लगाया गया है कि जनवरी में पांच फीसदी की गिरावट के बावजूद फरवरी में हमारी अर्थव्यवस्था साल 2019 के स्तर पर आ जाएगी। असंगठित क्षेत्रों की हालत कितनी बिगड़ी हुई है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि एक महीने पूर्व सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की 20 फीसदी इकाइयां अपना कर्ज वापस करने में सक्षम नहीं थीं। इसका अर्थ है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र की बुनियाद पर ही संगठित क्षेत्र आगे बढ़ सकता है। साफ है, दो महीने की तुलना में अभी जीडीपी दर बेशक ज्यादा है, लेकिन साल 2019 के बनिस्बत यह अब भी काफी कम है। लॉकडाउन के समय हमारे यहां उत्पादन में लगभग 75 फीसदी की गिरावट आई थी, और यह अब भी 10 फीसदी कम है। इसलिए अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में हम अप्रत्याशित वृद्धि भी देख सकते हैं। लेकिन इसको अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर तो नहीं ही कहेंगे।

प्रवीण कुमार सिंह

देश का विकास तभी संभव जब योग्य नेताओं को नीति निर्माण में मिले पर्याप्त अवसर

हमारे नेताओं की मौजूदी पीढ़ी उन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के प्रति निष्ठुर है जिन्होंने हमें राजनीतिक स्वतंत्रता की सौगात दी। उन सेनानियों ने इन भावी नेताओं पर ही आर्थिक विपन्नता को मिटाने और गरिमा एवं सम्मान से जीने को संभव बनाने का दारोमदार सौंपा था। यह तभी संभव है जब भद्र एवं योग्य नेताओं को निर्णय प्रक्रिया एवं नीति निर्माण में पर्याप्त अवसर मिले। हाल में एक टिप्पणीकार के हवाले से मैंने पढ़ा कि हमारी युवा पीढ़ी को राजनीति एवं नेताओं पर भरोसा नहीं है। ऐसे में यह मतदाताओं के सम्मान और भरोसे को जीतने का समय है।

इतने बड़े पैमाने पर अज्ञानता और गरीबी होने के बावजूद भारत में लोकतंत्र का स्वरूप देखकर दुनिया को बड़ा अचंभा होता है। भारत 20वीं सदी में राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करने वाले चुनिंदा देशों में से एक है जहां मतदान के आधार पर ही रक्तहीन सत्ता हस्तांतरण हुआ है। लोकतंत्र के रूप में दुनिया में सबसे अधिक सराहे जाने वाले अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उलट भारत में मुख्य चुनाव अधिकारी के प्रमाण पत्र को सभी प्रत्याशी गरिमापूर्वक स्वीकार करते हैं। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पत्रिका 'द इकोनॉमिस्ट' ने भी अपने हालिया अंक में यह लिखा है कि भले ही भारत में कुछ संस्थानों का पराभव हो रहा हो, परंतु वहां लोकतंत्र का अस्तित्व अक्षुण्ण है।

स्वतंत्रता के बाद उच्च सरकारी पदों पर स्वतंत्रता सेनानी या अपने क्षेत्रों में महारत हासिल कर चुके भद्र लोग ही आसीन हुए। उन्होंने एक आधुनिक लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना कर नागरिकों की सेवा की। यह सेवा उन्होंने उस देशभक्ति के कारण की जो उनके मूल सिद्धांतों में शामिल थी। उनके शब्दों और फैसलों ने यही जाहिर किया। मुझे 1996 में अंडमान स्थित सेल्युलर जेल देखने का अवसर मिला जो 'काला पानी' के नाम से कुख्यात थी।

वहां स्वतंत्रता सेनानियों को भयावह प्रताड़नाएं दी जाती थीं। उनमें से तमाम ने भावी पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए अपना जीवन उन्हीं कष्टों में होम कर दिया। वहां उन सेनानियों से जुड़े रजिस्टर में दर्ज एक वाकये ने मुझे बहुत मर्माहत किया। वह एक ऐसे कैदी से जुड़ा था जिसे फांसी होने वाली थी। उसने रिहा हुए अपने साथी के जरिये गांव वालों को यही संदेश भिजवाया कि वह उन्हें यही बताए मैं अपना

फर्ज निभा चुका हूं और अब उन्हें अपना कर्तव्य निभाना होगा। उस दौरे में मेरी सबसे छोटी बेटी भी साथ थी जिसकी उम्र तब 15 वर्ष रही होगी। उसने मुझसे उस संदेश का मर्म समझाने को कहा। मैंने कहा कि संभव है कि गांव को उनका संबोधन मात्र एक प्रतीक हो और वह समूचे देश को यह संदेश देना चाहते हों कि उनके बलिदान से देश को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली और यह अगली पीढ़ियों की जिम्मेदारी है कि वे लाखों लाख गरीबों के आर्थिक उद्धार की लड़ाई लड़ें।

दक्षिण कोरिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे अधिकांश पूर्वी एशियाई देशों को भी 20वीं शताब्दी में आजादी मिली और उन्होंने व्यापक स्तर पर गरीबी दूर करके संपन्नता की राह पकड़ी है। वहीं भारत गरीबी उन्मूलन और आम आदमी को संपन्न बनाने की दिशा में अभी भी संघर्ष ही कर रहा है। वहीं बीते कुछ दशकों के दौरान भारतीय लोकतंत्र के संचालन में व्यापक गिरावट देखने को मिली है। जनप्रतिनिधियों और सरकार में महत्वपूर्ण पद संभालने वालों की गुणवत्ता को देखकर इसका स्पष्ट आभास होता है। बताया जाता है कि देश में फिलहाल 36 प्रतिशत सांसद और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। पारिवारिक मिल्कियत जैसे राजनीतिक दल, धार्मिक हितों से जुड़े समूह, धनबल-बाहुबल और उत्तराधिकार की महत्ता खासी बढ़ गई है। यहां तक कि अगर कुछ विषय विशेषज्ञ पेशेवरों को भी सरकार में महत्वपूर्ण पद मिलते हैं तो अधिकांश मामलों में वे भी पद प्रदान करने वाली पार्टी के अहसान तले ही दबे रहते हैं और किसी वाजिब मसले पर एक राजनेता के रूप में अपनी आवाज बुलंद करने से हिचकते हैं। प्रत्येक विधानसभा और आम चुनाव में यह दिखता भी है। हालिया बिहार विधानसभा चुनाव भी इसका गवाह बना।

बहरहाल सार्वभौमिक मताधिकार और एक व्यक्ति-एक मत वाले उस लोकतंत्र में जहां अशिक्षा और आर्थिक विपन्नता व्यापक रूप से पसरी हुई हो, वहां बड़ी संख्या में अयोग्य व्यक्तियों के चुने जाने की संभावनाएं एवं गुंजाइश काफी बढ़ जाती हैं। ऐसे में सक्षम, ईमानदार और प्रेरित करने वाले नेताओं के लिए पर्याप्त जगह बनानी होगी। हालांकि अनुभवजन्य साक्ष्यों के अभाव में ऐसे नेताओं की कमी के कारण तलाशना कठिन है, वह भी तब जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी पिछड़ी हुई है और लाखों लोग आर्थिक मुश्किलों को झेल रहे हैं। इसके बावजूद कृषि सुधारों जैसे मसलों पर राजनीतिक सहमति बन पाना मुश्किल है। यह स्थिति तब है जब हर एक नेता गरीब किसानों के कल्याण की कसमें खाकर नमक का हक अदा करने का दावा करता है।

हमें यह नहीं भूलना होगा कि ढांचागत सुधारों के अभाव में संस्थागत सुधार अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह फलदायी नहीं हो सकते। आइबीसी इसका एक उदाहरण है। संस्थागत सुधारों में जहां गड़बड़ियां और निहित स्वार्थ बेलगाम होते हैं, सभी पक्षों की सहमति के अभाव में उनकी राह खुल पाना असंभव होगा।

उधर सत्ता में आने पर प्रत्येक राजनीतिक दल और उसके मंत्री बने नेता यही दावा करते हैं कि उनका हर एक कदम गरीबों के हित में उठाया गया है। इसके साथ ही 'प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद' का पिटारा खुलता ही जाता है। फिर उसके तात्कालिक और दीर्घकालिक आर्थिक परिणामों की परवाह नहीं की जाती। असल में अधिकांश समय तो संकीर्ण राजनीतिक हितों की पूर्ति में ही लग जाता है। वे एक मामूली नेता (पॉलिटिशियन) और महान राजनेता (स्टेट्समैन) के बीच अंतर को समझने से ही इन्कार करते हैं। जबकि सरकार में होने का तकाजा ही यही होता है कि नेता एक राजनेता के रूप में उभरकर अधिक से अधिक लोगों की भलाई के लिए कदम उठाएं, न कि अपने राजनीतिक दल के हितों को पोषित करें। अफसोस की बात यही है कि परिपक्व लोकतंत्रों में भी राजनेताओं की प्रजाति धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही है।

हमारे नेताओं की मौजूदी पीढ़ी उन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के प्रति निष्ठुर है जिन्होंने हमें राजनीतिक स्वतंत्रता की सौगात दी। उन सेनानियों ने इन भावी नेताओं पर ही आर्थिक विपन्नता को मिटाने और गरिमा एवं सम्मान से जीने को संभव बनाने का दारोमदार सौंपा था।

यह तभी संभव है जब भद्र एवं योग्य नेताओं को निर्णय प्रक्रिया एवं नीति निर्माण में पर्याप्त अवसर मिले। हाल में एक टिप्पणीकार के हवाले से मैंने पढ़ा कि हमारी युवा पीढ़ी को राजनीति एवं नेताओं पर भरोसा नहीं है। ऐसे में यह मतदाताओं के सम्मान और भरोसे को जीतने का समय है। भारत ने लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा की है तो अब इस मोर्चे पर परिणाम भी दिखने चाहिए।

लोकतंत्र में इंटरनेट मीडिया की चुनौतियां, कानूनी शिकंजा कसा जाना समय की मांग

हाल ही में यह प्रकाश में आया है कि कैंब्रिज एनालेटिका नामक एक कंपनी ने 8.7 करोड़ लोगों के फेसबुक डाटा के आधार पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव अभियान में काम किया और ट्रंप की जीत में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रश्न यह है कि इस कंपनी को फेसबुक का डाटा कहां से मिला, तो यह बात स्पष्ट है कि वो फेसबुक से ही प्राप्त किया गया। वर्ष 2018 में यह बात सामने आई थी कि इसी कैंब्रिज एनालेटिका ने भारत की कांग्रेस पार्टी के लिए फेसबुक और ट्विटर के डाटा का उपयोग कर 2019 के चुनावों के लिए मतदाताओं के रुझान को बदलने के लिए कार्य करने का प्रस्ताव रखा।

राजनीतिक दलों के लिए चुनावों की दृष्टि से इंटरनेट मीडिया कंपनियों के डाटा का दुरुपयोग एक सामान्य बात मानी जाने लगी है। लेकिन हालिया अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इन कंपनियों का दखल बढ़ गया है। ट्रंप की लगभग सभी ट्वीट पर ट्विटर कंपनी की टिप्पणी आ रही थी। ट्रंप के सभी बयानों को संदेहास्पद बनाने में इस कंपनी की भूमिका रही। अमेरिका में हुए हालिया हिंसक प्रदर्शनों के बाद ट्रंप का ट्विटर एकाउंट सस्पेंड करने के कारण यह कंपनी विवाद का केंद्र बन गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इन कंपनियों

के पास इन प्लेटफार्म्स को इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की निजी जानकारियां बड़ी मात्र में होती हैं। ये कंपनियां उनके सामाजिक रिश्तों, जात-बिरादरी, आर्थिक स्थिति, उनकी आवाजाही व खरीदारियों समेत तमाम प्रकार के डाटा पर अधिकार रखती हैं और इसका उपयोग वे राजनीतिक दलों के हितसाधन में भी कर सकती हैं। ऐसे में वे प्रजातंत्र को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि इंटरनेट मीडिया का उपयोग ईमानदारी से किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि ये राजनीति को प्रभावित करने का व्यवसाय करने लगें, तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ही नहीं, बल्कि सामाजिक तानाबाना भी खतरे में पड़ जाएगा।

गौरतलब है कि अकेले भारत में ही फेसबुक के 33.6 करोड़ से ज्यादा खाते हैं, जबकि इस कंपनी द्वारा चलाई जा रही मैसेजिंग, वायस एवं वीडियो कॉल एप्स के 40 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं। इसी प्रकार फेसबुक इंस्टाग्राम एप की भी मालिक है, जो फोटो और वीडियो साझा करने की एक लोकप्रिय एप्लीकेशन है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की एक बड़ी आबादी का निजी, आर्थिक एवं सामाजिक डाटा इस कंपनी के पास है। इसी प्रकार भारत में ट्विटर के लगभग सात करोड़ और दुनिया में 33 करोड़ खाते हैं। फेसबुक, वाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंकडइन आदि हालांकि मुफ्त में सेवाएं प्रदान करती हैं, लेकिन अपने बड़े डाटाबेस का उपयोग वे अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए करती हैं। इसी प्रकार गूगल को भी इस तरह के अनेक मामलों में दोषी पाया गया है।

आज भारत में विज्ञापन की दृष्टि से गूगल और फेसबुक सर्वाधिक आमदनी कमाने वाली कंपनियां बन चुकी हैं। इसी प्रकार अन्य कंपनियों के भी अपने-अपने बिजनेस मॉडल हैं। ये कंपनियां उपभोक्ताओं को काफी संतुष्टि भी प्रदान कर रही हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लेकिन इनकी बढ़ती लोकप्रियता और इन पर किसी भी प्रकार के अंकुश के अभाव में इन कंपनियों से समाज के तानेबाने को बिगाड़ने और लाभ के लिए कार्य करते हुए प्रजातंत्र को प्रभावित करने की केवल आशंकाएं ही नहीं, बल्कि वास्तविक खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं।

स्क्रैपिंग नीति का टॉनिक

सोमवार को अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि केंद्र सरकार जल्द ही स्क्रैपेज पॉलिसी घोषित करने वाली है जिससे 20 साल से ऊपर की प्राइवेट गाड़ियां और 15 साल से ऊपर के कमर्शल और सरकारी वाहन सड़कों से हटेंगे और नई गाड़ियों की खरीद का रास्ता साफ होगा। बाद में भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी पुष्टि की कि ऑटो इंडस्ट्री की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए यह योजना लाई जा रही है। योजना से जुड़े सारे सारे प्रावधान तो इसके घोषित हो जाने के बाद ही स्पष्ट होंगे, लेकिन बजट भाषण के मुताबिक 15 साल पूरे कर चुके कमर्शल तथा सरकारी वाहनों और 20 साल पूरे कर चुकी निजी गाड़ियों की फिटनेस जांच होगी और इसमें फिट न पाई गई गाड़ियों के बदले नई गाड़ियां खरीदने पर सरकार की ओर से छूट मिलेगी।

सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से जहां ईंधन की बचत होगी और हवा का प्रदूषण कम होगा, वहीं ऑटो इंडस्ट्री में भी नई जान आ जाएगी।

चूंकि ऑटो सेक्टर कंस्ट्रक्शन के बाद नौकरी देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, इसलिए मौजूदा माहौल में यह सेक्टर उठ खड़ा हो तो पूरी इकॉनमी का चक्का फिर से तेज घूमने की संभावना बढ़ जाएगी। ऑटो सेक्टर के जरिए इकॉनमी की सुस्त पड़ती रफ्तार को तेज करने की कामयाब कोशिशें दस साल पहले भी हुई थीं। सरकार अगर इस नुस्खे को एक बार फिर आजमाना चाहती है तो इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। मगर ध्यान देने की बात यह है कि इस सेक्टर में सुस्ती भी कोई पहली बार नहीं आई है। 2012-13 में गाड़ियों की बिक्री में कमी आने लगी थी तो इसकी तेजी बनाए रखने के कई उपाय किए गए थे।बावजूद इसके, एक-दो साल बाद फिर गिरावट के ट्रेंड दिखाई देने लगे। यह भी कि कोरोना की खबरें आने से पहले ही यह सेक्टर गंभीर गिरावट की गिरफ्त में आ चुका था। 2018 में देश में कुल 44,00,136 मोटर गाड़ियां बिकी थीं लेकिन 2019 में यह आंकड़ा 38,16,891 तक ही सिमट गया।

बहरहाल, माना जा रहा है कि प्रस्तावित स्क्रैपेज पॉलिसी से बड़े पैमाने पर मांग पैदा होगी जो इस क्षेत्र के लिए टॉनिक का काम कर सकती है। संभवतः इस योजना के पीछे अमेरिका में बराक ओबामा की 2009 में लाई कैश फॉर क्लंकर्स (पुरानी गाड़ी जमा करने पर नकद सहायता) की प्रेरणा है जो वहां काफी कामयाब मानी गई थी। पर उस योजना में न तो जांच-पड़ताल के लिए कोई जगह रखी गई थ, ना ही नई गाड़ी खरीदने की कोई मजबूरी थी। पुरानी गाड़ी जमा करते ही कैश मिल जाता था। आप उस कैश का इस्तेमाल नई गाड़ी में खरीदने में करना चाहें या किसी और काम में, आपकी मर्जी। बेहतर होगा कि यहां भी सरकार कानूनी तंत्र के दबाव से लोगों को नई गाड़ियां खरीदने की ओर धकेलने के बजाय छूटों और सहूलियतों के जरिए उन्हें इस ओर खींचने का रास्ता अपनाए।

यदि राज्यसभा की एक सीट खाली के साथ भरी होने वाली स्थिति में है तो न्यायपालिका के कारण

ऐसी किसी प्राथमिकता का परिचय खुद न्यायपालिका की ओर से क्यों नहीं दिया जा रहा है? यह वह सवाल है, जिसका जवाब न्यायपालिका के अलावा और किसी के पास नहीं। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि न्यायपालिका जैसी अपेक्षा विधायिका के पीठासीन अधिकारियों से कर रही है, उसकी पूर्ति खुद नहीं कर पा रही है। जब विधानमंडलों के स्पीकर्स विधायकों और सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण करने में देरी करते हैं तब न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, लेकिन आखिर तब कोई क्या करे जब ऐसी देरी खुद न्यायपालिका के स्तर पर हो रही हो? इसका जवाब किसी के पास नहीं।

इन दिनों उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों के विधान परिषद चुनाव चर्चा में हैं। उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ आइएएस अधिकारी अरविंद शर्मा और बिहार में शाहनवाज हुसैन के चुनाव मैदान में आ जाने से यह चर्चा दिलचस्प हो गई है, लेकिन यहां प्रश्न विधान परिषद चुनावों का नहीं है। इसके पहले राज्यसभा चुनाव चर्चा में थे। तब बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की उम्मीदवारी ने इस संभावना को प्रबल किया था कि क्या वह केंद्र में मंत्री बनेंगे? पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, लेकिन वह उस राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार बने, जो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के चलते रिक्त हुई थी। यहां भी ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि लोक जनशक्ति पार्टी की राज्यसभा सीट भाजपा को कैसे मिल गई? प्रश्न यह है कि करीब तीन वर्षों से अधिक समय से रिक्त राज्यसभा की एक सीट भरने का नाम क्यों नहीं ले रही है? यह वह सीट है जो कभी शरद यादव के पास थी।

शरद यादव 2016 में जनता दल-यू की ओर से राज्यसभा सदस्य बने, लेकिन उन्हें यह रास नहीं आया कि उनके दल ने लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल से नाता तोड़कर भाजपा से हाथ मिला लिया। वह इस फैसले के खिलाफ न केवल खड़े हो गए, बल्कि लालू यादव के पक्ष में खुलकर बोलने भी लगे। इतना ही नहीं उन्होंने राजद की पटना रैली में हिस्सा भी लिया। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि इस तरह की गतिविधियों में भाग लेने से उनकी राज्यसभा सदस्यता के लिए खतरा नहीं पैदा हो जाएगा तो उनका कहना था कि

सिद्धांतों की लड़ाई के लिए राज्यसभा की सीट बहुत छोटी चीज है। वाकई वह सिद्धांतों की राजनीति के लिए जाने जाते रहे हैं।

वह उन समाजवादी नेताओं में से हैं जो गैर-कांग्रेसवाद की उपज हैं। अब वह कांग्रेस की भागीदारी वाले महागठबंधन का हिस्सा हैं। उनकी बेटी बिहार विधानसभा का चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर लड़ चुकी हैं, लेकिन यहां प्रश्न उनकी राजनीतिक विचारधारा का नहीं है। वैसे भी वह भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा रह चुके हैं। एक समय तो वह इस गठबंधन के संयोजक थे, लेकिन जब 2017 में नीतीश लालू से अलग हुए तो शरद यादव ने उनका साथ छोड़कर लालू का हाथ पकड़ा।

लालू की रैली में हिस्सा लेने के आधार पर जदयू ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से उनकी सदस्यता खारिज करने की मांग की। दिसंबर 2017 में नायडू ने उनकी सदस्यता खारिज कर दी। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने यह कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि असली जदयू वही हैं। यही दावा उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष भी किया था, लेकिन उसने उनके इस दावे को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता पर तो कोई फैसला नहीं दिया, लेकिन उन्हें सरकारी बंगले में रहने और वेतन-भत्ता लेने के योग्य करार दिया। इस फैसले के खिलाफ जदयू नेता सुप्रीम कोर्ट गए। वहां यह आदेश हुआ कि शरद यादव सरकारी बंगले में रह सकते हैं, लेकिन वेतन-भत्ता नहीं ले सकते। यह आदेश देते समय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को यह भी कहा था कि वह मामले का जल्द निपटारा करे, लेकिन मामला तारीख पर तारीख का शिकार है।

हालांकि तबसे शरद यादव अपनी नई पार्टी बना चुके हैं और राजद से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उनकी सदस्यता पर फैसले की नौबत नहीं आ रही है। चूंकि उनकी सदस्यता पर फैसला अटका है इसलिए उनकी सीट पर चुनाव भी नहीं हो पा रहा है। इस सीट के अधर में होने और उस पर चुनाव न होने से किसे क्या नुकसान हो रहा है, यह तो पीड़ित पक्ष ही जाने, लेकिन क्या इसका कोई तुक है कि यह न जाना जा सके कि यह सीट खाली है भरी?

नियमानुसार यदि राज्यसभा की सीट रिक्त हो जाए तो छह माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होता है, लेकिन शरद यादव राज्यसभा के सदस्य हैं भी और नहीं भी। हैं इसलिए, क्योंकि वह राज्यसभा सदस्य के तौर पर आवंटित बंगले में रह रहे हैं। नहीं इसलिए, क्योंकि वह राज्यसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते। कुल मिलाकर उनकी राज्यसभा सीट रिक्त भी है और नहीं भी है। यह विचित्र और रहस्यमय स्थिति सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बावजूद है कि विधायकों और सांसदों की अयोग्यता संबंधी मामलों का निपटारा जल्द होना चाहिए। उसके इस फैसले का असर भी हुआ और विधानसभा के अध्यक्षों ने विधायकों की अयोग्यता संबंधी मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करना शुरू कर दिया। ऐसी किसी प्राथमिकता का परिचय खुद न्यायपालिका की ओर से क्यों नहीं दिया जा रहा है? यह वह सवाल है, जिसका जवाब न्यायपालिका के अलावा और किसी के पास नहीं। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि न्यायपालिका जैसी अपेक्षा विधायिका के पीठासीन अधिकारियों से कर रही है, उसकी पूर्ति खुद नहीं कर पा रही है। जब विधानमंडलों के स्पीकर्स विधायकों और सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण करने में देरी करते हैं तब न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, लेकिन आखिर तब कोई क्या करे जब ऐसी देरी खुद न्यायपालिका के स्तर पर हो रही हो? इसका जवाब किसी के पास नहीं। कई मामलों में उच्चतर न्यायपालिका की ओर से यह कहा जाता है कि यदि कोई अपना काम सही तरह नहीं करेगा तो हम करेंगे। प्रश्न है कि यदि न्यायपालिका अपना काम सही से न करे तो कोई क्या करे?

शरद यादव का राज्यसभा का कार्यकाल जुलाई 2022 तक है। उनका मामला जिस तरह लंबा खिंच रहा है उससे तो यह लगता है कि कहीं जब तक फैसला आए तब तक जुलाई 2022 बीत न जाए। वैसे भी कई मामलों में ऐसा हो चुका है कि जब तक फैसला आया तब तक इतनी देर ही चुकी थी कि फैसला प्रतिवादी के पक्ष में आने के बाद भी वह उसका लाभ नहीं उठा सका।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

रिटायर्ड आईपीएसअफसर भवेश कुमार सिंह होंगे मुख्य सूचना आयुक्त, करीब एक वर्ष से पद खाली

लखनऊ । लम्बे समय से खाली पड़े मुख्य सूचना आयुक्त की कुर्सी पर रिटायर्ड आईपीएस अफसर बैठेंगे। भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी भवेश कुमार सिंह प्रदेश के अगले और चौथे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर चयन के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई तीन सदस्यीय समिति की बैठक में उनके नाम पर सहमति जता दी है। समिति की सिफारिश से संबंधित फाइल प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के लिए राजभवन भेज दी गई है। समिति ने जिन सात नामों पर विचार किया उनमें न्यायपालिका, भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी तथा आरटीआइ एक्टिविस्ट आदि शामिल थे। इनमें भवेश कुमार सिंह, जस्टिस (रिटायर्ड) अनिल कुमार, राजस्व परिषद अध्यक्ष आइएएस अधिकारी दीपक त्रिवेदी और वर्तमान में सूचना आयुक्त राजीव कपूर, दुष्यंत कुमार, ताहिर हसन नकवी, अशोक कुमार शुक्ला के नामों पर मंथन हुआ। बिहार के सुपौल के मूल निवासी भवेश कुमार सिंह भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश काडर के 1987 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। प्रदेश में वह अलीगढ़, मऊ, मथुरा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, प्रयागराज, बरेली और कानपुर में एसपी/एसएसपी तथा आगरा और गोरखपुर रेंज के आइजी रह चुके हैं। एक अगस्त 2017 को महानिदेशक (डीजी) के पद पर प्रमोट हुए थे। इसके बाद बीते साल वह डीजी इंटेलिजेंस के पद से रिटायर हुए। प्रदेश के तीसरे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त रहे जावेद उस्मानी का कार्यकाल 16 फरवरी 2019 को खत्म हुआ था। तब से यह पद खाली था। लंबे समय से इस पद पर नियुक्ति होने का मामला अदालत में भी पहुंचा। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी सरकार से इस बाबत जवाब तलब कर चुका है।

पश्चिम चंपारण : 08 वर्ष में अंधविश्वास की आग में तबाह हुई 241 महिलाओं की जिंदगी

बेतिया (पश्चिम चंपारण)। आजादी के वर्षों बाद भी हमारा समाज अंधविश्वास के मकड़जाल से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाया है। कहने को तो जिले में साक्षरता दर 58 फीसद है। लेकिन इसके विपरीत आए दिन अंधविश्वास के नाम पर महिलाओं के साथ प्रताड़ना व मारपीट की घटनाएं हो रही है। सोचने की बात यह भी है कि समय के साथ विज्ञान के विकास के बाद जिस आडंबर और अंधविश्वास का अंत होना चाहिए था वो अब तक नहीं हो सका है। आधुनिक व शिक्षित पीढ़ी भी इस मार्ग पर ही चलती है। काला जादू, भूत-प्रेत, डायन प्रथा अभी भी कायम है। आश्चर्यजनक पहलू यह है कि जैसे-जैसे जिले का साक्षरता दर बढ़ रहा है वैसे-वैसे लोगों को अंधविश्वास से दूर होना चाहिए लेकिन वे इसके हिमायती हैं। पिछले 8 वर्षों में अंधविश्वास के कारण जिले के विभिन्न थानों में डायन एक्ट के 241 मामले दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2007 में तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर मिश्र ने डायन एक्ट की एक मामले में 5 लोगों को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। 11 सितंबर 2007 को गांव की एक महिला को आरोपियों ने धोखे से घर पर बुलाया और कमरे में बंद कर मैला पिला दिया था। हालांकि उस वक्त कार्रवाई से गांव में हड़कंप की स्थिति थी लेकिन अभी भी इस तरह की घटनाएं हो रही है। कई बार लोक लाज और दबंगों के डर से प्रताड़ित महिलाएं थाने नहीं आती है। तो कुछ मामलों को पुलिस भी दबा देती है। थाने में आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। नतीजतन डायन का आरोप झेल रही महिलाएं समाज में परित्यक्त हैं। समाज के ताने से तंग कुछ महिलाएं तो आत्महत्या भी करने की कोशिश करती हैं। लोगों का मानना है कि अधिकतर मामलों में अंधविश्वास और गवाही राजनीति भी बहुत बड़ा कारण है। युवा अधिवक्ता राजू कुमार ओझा ने कहा कि आजादी के वर्ष बाद डायन जैसी सामाजिक बुराई समाज में आज भी कायम है। यह बुराई घटने की जगह बढ़ती ही जा रही है। जबकि इस एक्ट में कड़े दंड का कानूनी प्रावधान है। घरेलू हिंसा के कारण भी किसी महिला को डायन बताकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। सामाजिक रूप से जागरूकता फैलाकर इस सामाजिक बुराई से निपटा जा सकता है।इस बारे में चंपारण रेंज डीआईजी ललन मोहन प्रसाद ने कहा कि महिलाओं पर डायन का आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित करना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में पुलिस दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करती है। ऐसे कई मामले है जिनमें दोषियों को सजा दिलाई गई है। डायन एक्ट से जुड़े मामलों की पूरी गंभीरता से साथ जांच पड़ताल की जाती है।

नवांशहर के स्कूल 5 और बच्चे मिले संक्रमित, कल आई थी तीन शिक्षकों सहित 14 की रिपोर्ट पाजिटिव

नवांशहर । नवांशहर के सरकारी स्कूल सलोह के 3 अध्यापकों व 14 बच्चों की रिपोर्ट मंगलवार को पाजिटिव आने के बाद बुधवार को भी 5 बच्चों की कोरोना रिपोर्ट पाजिटिव आई है। इन बच्चों को इनके घर में ही आइसोलेट कर दिया गया है। यह सभी बच्चे कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक के बताए जाते हैं। पांच बच्चों के इसी स्कूल से फिर से पाजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। स्कूल को मंगलवार को ही अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद कर दिया गया था। मंगलवार को 110 बच्चों के सैंपल ले लिए गए थे पर करीब 60 विध्यार्थियों के सैंपल नही लिए जा सके हैं। अब रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शिक्षा विभाग से तालमेल कर बाकि बचे बच्चों के घर के पते पता कर रहे हैं और उनके घर जाकर बच्चों के सैंपल लिए जा रहे हैं। सिविल सर्जन डा.गुरदीप सिंह कपूर का कहना है कि जैसे ही 5 बच्चों के पाजिटिव आने की सूचना मिली तभी से स्वास्थ्य कर्मियों को बाकि बच्चों के भी सैंपल को जल्द से जल्द लेने के लिए कह दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है। बेशक बच्चों में लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। बता दें कि नवांशहर में सराकारी स्कूल सोलह में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब वहां कोरोना वायरस संक्रमण के कई मामले सामने आ गए। स्कूल के 14 विद्यार्थी और तीन अध्यापक कोरोना पाजिटिव पाए गए। इससे पहले रविवार को स्कूल की मुख्य अध्यापिका की रिपोर्ट कोरोना पाजिटिव आई थी। इसके बाद सोमवार को स्कूल के विद्यार्थियों और अध्यापकों के सैंपल लिए गए थे। मंगलवार को इसमें से 14 विद्यार्थी व तीन अध्यापकों की रिपोर्ट कोरोना पाजिटिव आई।

अब हरिद्वार से वाराणसी तक बनेगा गंगा एक्सप्रेस-वे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लंबाई बढ़ाने के दिए निर्देश

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में बनने जा रहे देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस-वे को योगी सरकार और विस्तार देने जा रही है। यूपी सरकार गंगा एक्सप्रेस-वे की लंबाई बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज से बढ़ा कर वाराणसी और मेरठ से बढ़ा कर हरिद्वार तक करने की तैयारी है। वहीं, सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की लंबाई भी बढ़ाने जा रही है। इसको बलिया तक ले जाने की योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेस वे के विस्तार का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

केंद्र सरकार के आम बजट में हाइवे और एक्सप्रेस-वे निर्माण कार्यों को और विस्तार देने की योजना को देखते हुए योगी सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेस-वे को मेरठ से बढ़ाकर हरिद्वार तक और प्रयागराज से वाराणसी तक विस्तार देने का प्रस्ताव जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। विस्तार के प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई करीब 150 किलोमीटर तक बढ़ने की उम्मीद है। प्रयागराज से वाराणसी तक के विस्तार में गंगा एक्सप्रेस-वे के जरिये पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र के कई जिलों में विकास की नई राह खुलना तय है। गंगा एक्सप्रेस-वे वाराणसी के साथ मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र और चंदौली को भी जोड़ेगा। एक्सप्रेस वे विस्तार के साथ ही इन क्षेत्रों में उद्योग और पर्यटन के विकास की उम्मीदों को भी विस्तार मिलना तय माना जा रहा है।

मौजूदा समय में गंगा एक्सप्रेस-वे की लंबाई कुल 596 किलोमीटर तय की गई है, जिसके निर्माण की अनुमानित लागत 36,402 करोड़ रुपये तय की गई है। मौजूदा योजना के मुताबिक गंगा एक्सप्रेस-वे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली, प्रतापगढ़ से होते हुए प्रयागराज तक पहुंचेगा। एक्सप्रेस-वे के निर्माण का जिम्मा यूपीडा के पास है। गंगा एक्सप्रेस-वे छह लेन का होगा, जिसे भविष्य में आठ लेन तक बढ़ाया जा सकेगा।

आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी को एक्सपोर्ट हब बनाने की योजना और आम बजट में एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट को विस्तार देने के प्राविधान को देखते हुए योगी सरकार ने वाराणसी के जरिये पूर्वांचल की दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों से कनेक्टविटी को मजबूत करने के लिए गंगा एक्सप्रेस-वे को विस्तार देने की योजना पर काम कर रही है। ताकि कोलकाता से लेकर दिल्ली तक वाराणसी और प्रयागराज समेत प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

योगी सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की लंबाई भी बढ़ाने जा रही है। निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को बलिया तक ले जाने की योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के विस्तार का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि केंद्र सरकार से सहायता ली जा सके।

गोंडा में बेटे की इस डिमांड को पिता ने ठुकराया, सोते वक्त पिता को ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से काट डाला

गोंडा । उत्तर प्रदेश के गोंडा के पिता की सोते समय कुल्हाड़ी मार कर हत्या कर दी गई। किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक के भतीजे की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा किया है। साथ ही आरोपित बेटे को हिरासत में लिया गया है। एक हजार रुपये के खातिर हत्या किए जाने की बात सामने आई है।

मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के दत्तनगर विशेन गांव का है। यहां के निवासी ईश्वरदीन(62) रेलवे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। करीब दो वर्ष पूर्व रिटायर हुआ था। आए दिन ईश्वरदीन व बेटे सुकई के बीच रुपये को लेकर कहासुनी होती रहती थी। मृतक ईश्वरदीन के भतीजे सुंदर के मुताबिक, मंगलवार को चाचा ईश्वरदीन अपने बेटे सुकई के साथ बैंक से पैसा निकालकर लाए थे। इस दौरान सुकई ने उनसे रुपये की मांग की। चाचा ने नाराजगी जताते हुए रुपये देने से इन्कार कर दिया। देर रात सोते समय सुकई ने कुल्हाड़ी से अपने पिता पर कई वार कर हत्या कर दी। नगर कोतवाल आलोक राव ने बताया कि हत्या का मुकदमा किया गया है। आरोपित बेटे सुकई को हिरासत में लेकर जानकारी की जा रही है। कुल्हाड़ी बरामद हुई है।

एक हजार के खातिर की हत्या : रिटायर होने के बाद ईश्वरदीन को करीब 18 लाख रुपये मिले थे। परिवार खुशहाल था। उसने बेटा व बेटियों का विवाह भी किया। सुकई के बच्चे भी हैं। सुकई बेरोजगार था। उसकी गलत संगत होने के कारण उसका पिता नाराज रहता था। मंगलवार को उसने एक हजार रुपये अपने पिता से मांगे थे। रुपये नहीं मिले तो उसने रात में पिता की हत्या कर दी। कलयुगी बेटे की करतूत को लेकर गांववासी स्तब्ध है। बेटियां व रिश्तेदारों का रो-रोकर हाल बेहाल है। गांव के लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं।

कैबिनेट विस्तार में दलित के साथ जाट पर दांव लगा सकती है योगी सरकार, मंत्री पद की रेस में कई नेता

मेरठ । विधानसभा चुनावों से पहले टीम योगी अंतिम मंत्रिमंडल के विस्तार की ओर बढ़ रही है। पीएमओ से वरिष्ठ आइएएस अधिकारी एके शर्मा को एमएलसी बनाने के बाद उन्हें बड़ा ओहदा मिलना तय माना जा रहा है, वहीं पश्चिम यूपी की धरती पर किसान आंदोलन का पारा गरमाने से यहां से भी नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। मेरठ के कई चेहरों पर उम्मीदें नजर आ रही हैं। हालांकि पश्चिम यूपी से मंत्री बनाए गए कई नामों पर गाज गिरने की भी चर्चा है।

अश्विनी बनाम एके शर्मा

विस चुनावों में करीब एक साल का वक्त बचा है। टीम योगी में एक बार फिर बड़े फेरबदल की तैयारी है। गत दिनों पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार के मूड में नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय के आइएएस अधिकारी एके शर्मा को यूपी से एमएलसी बनाने के बाद हलचल तेज हो गई है। शर्मा को एमएलसी के सेक्टर का मास्टर माना जाता है, ऐसे में उन्हें यह पोर्टफोलियो मिल सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा वेस्ट यूपी का लेकर है। यहां से कैबिनेट मंत्री के रूप में चौ. भूपेंद्र चौधरी और सुरेश राणा हैं, जबकि अतुल गर्ग, कपिल देव अग्रवाल, अनिल शर्मा, विजय कश्यप और अशोक कटारिया राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार के हैं।

पार्टी में उठ रही चर्चाओं के मुताबिक प्रदेश सरकार इनमें से कई मंत्रियों के प्रदर्शन से खुश नहीं हैं, ऐसे में उन्हें हटाकर नए नामों को मंत्री बनाया जा सकता है। हाल में एमएलसी बनाए गए अश्विनी त्यागी को भी मंत्री बनाने की बात उठ रही है। इस बहाने पार्टी एक त्यागी को टीम योगी में भेजकर बड़ा संदेश दे सकती है, लेकिन पार्टी उन्हें प्रदेश महामंत्री होने के नाते संगठन में रखने पर जोर देगी। साथ ही जातीय समीकरण देखें तो भूमिहार जाति से आने वाले पूर्व आइएएस अधिकारी एके शर्मा को बढ़त मिलती नजर आ रही है।

दलित के साथ जाट पर दांव

मेरठ के हस्तिनापुर विधायक दिनेश खटीक को अनूसूचित होने के साथ ही संघ के करीबी होने का फायदा मिल सकता है। दिनेश अपनी विस में लोगों के हक के लिए लड़ने वाले विधायक माने जाते हैं। जाट नेता के रूप में छपरौली विधायक सहेंद्र सिंह का नाम भी रेस में चल रहा है। इस बहाने भाजपा किसान आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल होने वाले जाटों को साधेगी।

यह विस चौ. चरण सिंह एवं उनके परिवार का गढ़ रहा है, जहां से निकलने वाला संदेश पूरे वेस्ट यूपी के किसानों के बीच पहुंचेगा। किसान आंदोलन में बड़े चेहरे बनकर उभरे राकेश टिकैत और रालोद की ओर से इसे हवा दे रहे जयंत चौधरी भी जाट हैं, ऐसे में भाजपा एक तीर से तीन निशाने साधेगी। राजनीतिक पंडितों की मानें तो एक गुर्जर चेहरे पर भी पार्टी में मंथन चल रहा है।

दिल्ली बॉर्डर पर सख्त बैरिकेडिंग को बसपा चीफ मायावती ने बताया अनुचित, बोलीं- किसानों के बजाए आतंकियों को ऐसे रोकें

लखनऊ । बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर कंटीले तारों और कीलें आदि वाली जबर्दस्त बैरिकेडिंग को अनुचित बताया है। उन्होंने कहा है कि इनकी बजाए यदि आतंकियों आदि को रोकने के लिए ऐसी कार्रवाई देश की सीमाओं पर हो तो यह बेहतर होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि किसानों की मांग पूरी करके स्थिति सामान्य करें। बसपा प्रमुख मायावती ने बुधवार को दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस की सख्त बैरिकेडिंग को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी की वाजिब मांग को लेकर खासकर दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलित किसानों के प्रति सरकारी रवैये के कारण संसद के बजट सत्र में भी जरूरी कामकाज और जनहित के खास मुद्दे पहले दिन से ही काफी प्रभावित हो रहे हैं। केंद्र किसानों की मांग पूरी करके स्थिति

सामान्य करे। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने अगले ट्वीट में आगे लिखा कि लाखों आंदोलित किसान परिवारों में दहशत फैलाने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर जो कंटीले तारों और कीलों आदि वाली जबर्दस्त बैरिकेडिंग की गई है वह उचित नहीं है। इनकी बजाए यदि आतंकियों आदि को रोकने हेतु ऐसी कार्रवाई देश की सीमाओं पर हो तो यह बेहतर होगा। बता दें कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली में उपद्रव से सबक लेते हुए पुलिस प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। टीकरी व सिंघु समेत दूसरे राज्यों को जोड़ने वाले दिल्ली के बॉर्डर पर कहीं चौड़े गड्ढे खोदे गए हैं तो कहीं सड़क पर नुकीली कीलें का तार लगाए गए हैं। जगह-जगह सीमेंट के बैरिकेड भी लगाए गए हैं। पुलिस की पूरी कोशिश है कि दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारी किसी भी हाल में दिल्ली में नहीं घुस सकें।

किसानों के खिलाफ 39 मामले दर्ज : कृषि कानून विरोधी किसानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने पिछले साल सितंबर से दिसंबर के बीच 39 मामले दर्ज किए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार दिल्ली पुलिस ने विरोध के दौरान एक आत्महत्या का मामला भी दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर यह भी बताया गया कि दिल्ली की सीमा पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में प्रदर्शनकारी किसानों के बड़े काफिले ने उग्र तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की और पुलिस बैरिकेडिंग पर जबरन चढ़ गए। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कर्मचारियों को अपने कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए धींगामुश्ती की गई जिससे कई पुलिस कर्मियों को चोटें आईं।

यूपी बोर्ड के कोर्स में शामिल होगा चौरी चौरा कांड, सीएम योगी के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी

लखनऊ । उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की किताबों में अब चौरी चौरा कांड के शहीदों की वीरगाथाओं को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग चौरी चौरा की घटना को यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल करने जा रहा है। सीएम योगी ने चौरी चौरा जनआक्रोश को शताब्दी समारोह के रूप में मनाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में पहले चरण में गोरखपुर मंडल के 400 से अधिक राजकीय और एडेड माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को चौरी चौरा स्थल का भ्रमण कराया जाएगा। इससे छात्र वहां के शहीदों की गाथाओं से रूबरू हो सकेंगे।

गोरखपुर के चौरी चौरा में चार फरवरी, 1922 में आजादी के वीर जवानों ने अंग्रेजी हुकूमत से भिड़ंत के बाद पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। इस घटना को चौरी चौरा जनआक्रोश के रूप में जाना जाता है। शहीदों के इसी शौर्य की कहानी को अब यूपी बोर्ड में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। इससे प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले लाखों छात्र चौरी चौरा जनक्रांति में शहीद अपने वीरों के इतिहास से रूबरू हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग छात्रों को न सिर्फ वीरों के इतिहास को पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाएगा बल्कि छात्रों को शहीदों के स्थल चौरी चौरा का भ्रमण भी कराएगा। पहले चरण में गोरखपुर मंडल के देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर व गोरखपुर के 87 राजकीय विद्यालयों, 333 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय के छात्रों को चौरी चौरा शहीद स्थल का भ्रमण कराया जाएगा। इसमें मंडल के निजी स्कूलों को भी शामिल किया जाएगा।

छात्रों के बीच होंगी प्रतियोगिताएं : चौरी चौरा शताब्दी समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में चार फरवरी, 2021 से आगामी एक साल तक छात्र-छात्राओं के बीच निबंध, चित्रकला व पोस्टर, क्विज, स्लोगन, कविता लेखन व भाषण प्रतियोगिताएं भी कराई जाएंगी। इसके लिए पहले विद्यालय स्तर से शुरुआत होगी। फिर यह क्रम राज्य स्तर तक जारी रहेगा। तीन फरवरी, 2022 को गोरखपुर में मंडल स्तरीय प्रतियोगिता कराई जाएगी।

यूपी उपभोक्ता फोरम का फैसला:किसान मुलायम सिंह को 20 साल बिजली कनेक्शन न देने पर लगाया ढाई लाख का जुर्माना

फीरोजाबाद । फीरोजाबाद जिले में जसराना क्षेत्र के गांव सैदई के किसान मुलायम सिंह का 20 वर्ष का संघर्ष आखिर रंग लाया है। वर्ष 2000 से नलकूप के कनेक्शन के लिए भागदौड़ कर रहे मुलायम सिंह को अब कनेक्शन भी मिलेगा और वर्ष 2001 से कनेक्शन मिलने तक की अवधि का एक हजार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से धनराशि भी मिलेगी। विद्युत उपभोक्ता फोरम निवारण फोरम आगरा ने विद्युत विभाग को कनेक्शन जारी करने और एक हजार रुपये प्रति माह (यह धनराशि अब तक करीब ढाई लाख रुपये होगी) क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।

किसान मुलायम सिंह ने जनवरी 2000 में निजी नलकूप का विद्युत कनेक्शन लेने को आवेदन किया था। तत्कालीन एक्सईएन विद्युत वितरण खंड शिकोहाबाद के आदेश पर उन्होंने तत्कालीन एक्सईएन विद्युत वितरण छह फरवरी, 2001 को 1250 रुपये (कनेक्शन फीस) और 21 नवंबर, 2001 को 15419 (लाइन डालने की धनराशि) रुपये जमा करा दिए। कनेक्शन मिलने की उम्मीद में 70 हजार रुपये खर्च कर नलकूप भी स्थापित करा लिया। तब से वह डीजल से नलकूप चला रहे हैं। उन्हें अब तक कनेक्शन नहीं मिला।

आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगा विभाग : किसान मुलायम सिंह के अनुसार 20 साल की अवधि में उन्होंने कई बार विभागीय अधिकारियों के अलावा डीएम को भी शिकायती पत्र दिए। कई बार तत्काल कनेक्शन के आदेश भी हुए, लेकिन अमल कभी नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें उपभोक्ता फोरम की शरण लेनी पड़ी। फीरोजाबाद ग्रामीण के अधीक्षण अभियंता एके वर्मा का कहना है कि फोरम के आदेश के खिलाफ वह हाई कोर्ट जाएंगे।

तीन माह में सुनाया फैसला : किसान मुलायम सिंह ने अक्टूबर 2020 में फोरम की शरण ली। फोरम ने 30 दिसंबर, 2020 को फैसला सुनाया। फोरम के अध्यक्ष विजेंद्र कुमार ने बिजली विभाग को कनेक्शन न देने का दोषी मानते हुए कनेक्शन देने और 10 फरवरी, 2001 से कनेक्शन देने तक प्रतिमाह एक हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।

20 साल में हर किसी से की फरियाद : मुलायम सिंह के पुत्र अशोक आर्य अशोक का कहना है कि शुरू के 10 साल उनके पिता ने कनेक्शन चालू कराने के लिए काफी संघर्ष किया। उनके बुजुर्ग होने के बाद दस साल से वह प्रयास कर रहे हैं।

नुकसान की भरपाई को मिलेगी क्षतिपूर्ति : फोरम ने अपने आदेश में यह माना है कि 20 साल तक कनेक्शन न मिलने से उपभोक्ता को काफी मानसिक क्षति हुई। वहीं डीजल से नलकूप चलाने के कारण उसे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। इसकी भरपाई को क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिए हैं। इसका समायोजन कनेक्शन के बिल भुगतान में किया जाएगा।

बिहपुर दुष्कर्म कांड : आ गया फैसला, विशेष न्यायाधीश ने आरोपित को दी यह कठोर सजा

भागलपुर । पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश एमपी सिंह ने बुधवार को चर्चित बिहपुर दुष्कर्म कांड में दोषी प्रभाष चौधरी को आजीवन कारावास दे दी है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी देने का आदेश दिया है। इस मामले में शेष चार आरोपितों को न्यायाधीश ने पूर्व की सुनवाई में साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था। अभियुक्त को न्यायालय कक्ष में 11.30 बजे कड़ी सुरक्षा में लाया गया था। सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बहस में भाग लिया।

बिहपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर इलाके में 22 जनवरी 2017 को दस साल की बच्ची के साथ प्रभाष ने दुष्कर्म को अंजाम दिया था। तब बच्ची की मां का उपचार कराने उसके पिता भागलपुर डॉक्टर के पास गए हुए थे। तब घर पर बच्ची अकेली थी।

जिसकी जानकारी पाकर अभियुक्त ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। उस दौरान सुधो चौधरी, प्रह्लाद चौधरी और गोदो चौधरी आदि भी उसके साथ थे। जिनके विरुद्ध साक्ष्य नहीं होने के कारण न्यायालय ने सुनवाई के दौरान रिहा कर दिया। घटना के बाद इलाके में काफी हंगामा हुआ था। मामले में तब गांव में पंचायत बैठी थी। घटना के बाद झंडापुर निवासी प्रभाष चौधरी को बचाने के लिए और मामले को थाने तक नहीं ले जाने को लेकर काफी दबाव बनाया गया था।

एयरलाइंस अधिकारी रूपेश को आदर्शनगर के रीतुराज ने मारी थी गोली

बिहार । पटना एयरपोर्ट पर तैनात इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारी रूपेश कुमार सिंह की हत्या के मामले का पर्दाफाश हो गया है। पटना पुलिस के मुताबिक रूपेश की हत्या रोडरेज को लेकर हुई थी। रूपेश की हत्या 12 जनवरी की शाम 6.58 बजे हुई थी। पटना के एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि रूपेश को छह गोलियां लगी थीं। सभी गोलियां रूपेश को दाहिनी तरफ ही लगी थीं। आदर्श नगर रोड नंबर दो निवासी मनोरंजन के बेटे रीतुराज को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इसी शख्स ने रुपेश को गोलियां मारी थीं। इस मामले में रीतुराज के तीन और साथियों की तलाश में पुलिस लगी

है। ये तीनों भी पटना के ही रहने वाले हैं।

इस मामले में जांच के लिए एक एसआइटी गठित की गई थी। इसके अलावा पटना पुलिस की एक और टीम को भी जांच में लगाया गया था। इस मामले में 50 से अधिक लोगों से व्यक्तिगत तौर पर पूछताछ की गई। करीब 600 मोबाइल नंबरों की डिटेल को खंगाला गया। शुरू में पुलिस ने एक टेंपो स्टैंड के विवाद, ठेकेदारी के विवाद जैसे एंगल से पुलिस ने जांच की। जमीन के धंधे को लेकर भी पुलिस ने छानबीन की। एसएसपी ने बताया कि इस मामले में एक टेक्निकल टीम एसआइटी से हटकर लगातार जांच करती रही।

एसएसपी ने बताया कि जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि रुपेश को गोली मारने के लिए चार अपराधी दो बाइकों पर सवार होकर आए थे। इनमें से एक बाइक बजाज पल्सर, जबकि दूसरी बाइक टीवीएस अपाचे थी। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी बेली रोड से होकर आर ब्लॉक-दीघा रोड होकर दीघा की तरफ जाकर महेशनगर, इंद्रपुरी, राजीवनगर नाला, आशियाना-दीघा रोड से दोबारा बेली रोड होते हुए रुकनपुरा तक गए थे। इसके बाद पुलिस को इनके भागने का रूट पता नहीं चल सका।इसके बाद पुलिस ने उनके आने का रूट खंगालना शुरू किया तो पता चला कि ये अपराधी शाम को तीन बजे ही राजवंशीनगर मंदिर के पास दिखे थे। इसके बाद पुलिस की टेक्निकल टीम ने उनके आने का रूट खंगालते हुए कुर्जी कन्हैयानगर तक पहुंची। चारों अपराधी करीब ढाई बजे इसी जगह से राजवंशीनगर जाने के लिए निकले थे। कुर्जी कन्हैयानगर में सीसीटीवी फुटेज को लगातार खंगालने पर पता चला कि चारों अपराधियों में से कम से कम एक शख्स इसी इलाके का रहने वाला है।

बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा फरमान- हिंसक प्रदर्शन किया तो नहीं मिलेगी नौकरी, सियासत गरमाई

बिहार । बिहार में अब सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया तो खैर नहीं है। सोशल मीडिया पर मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों तथा सरकारी अधिकारियों पर अमर्यादित टिप्पणी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई के सरकार के आदेश की आलोचना हो ही रही थी कि अब बिहार पुलिस ने नया आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत सरकार के खिलाफ हिंसक धरना-प्रदर्शन करने वालों को सरकारी नौकरी या ठेका नहीं मिलेगा। सरकार के इस आदेश पर सियासी बयानबाजी तेज होती दिख रही है।

बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने

अपने पत्र में आदेश जारी किया है कि विधि व्यवस्था की समस्या पैदा करने वालों, सड़क जाम एवं धरना-प्रदर्शन के दौरान आपराधिक कृत्य में शामिल लोगों के खिलाफ अगर पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देती है, तब उन्हें सरकारी नौकरी या ठेके के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। आदेश के अनुसार उनके चरित्र प्रमाण पत्र में इसे स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना है।

विदित हो कि पटना में इंडिगो एयरलाइंस के एयरपोर्ट मैनेजर रूपेश सिंह की हत्या में ठीकेदारी विवाद की बात सामने आने के बाद सरकारी ठीके में चरित्र सत्यापन पर बल दिया गया था। इस बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया था कि सरकारी ठेके में चरित्र सत्यापन जरूरी होगा। उक्त बैठक में डीजीपी भी शामिल हुए थे। इसके बाद अब पुलिस मुख्यालय ने यह आदेश जारी किया है।

बिहार में गरमाई सियासत

पुलिस के इस आदेश पत्र पर बिहार में सियासत गर्म होती दिख रही है। विपक्ष इसे आम जनता के सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन मान रहा है तो सत्ता पक्ष इसे कानून व्यवस्था के हित में उठाया गया कदम बता रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने इसे लेकर अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना हिटलर व मुसोलिनी से करते हुए सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि युवा शक्ति से घबराई बिहार सरकार युवाओं को डराना चाहती है।

एक नजर

भाजपा सांसद ने आंध्र प्रदेश में हिंदू मंदिरों पर हमलों का मामला राज्यसभा में उठाया, बोले- राज्य सरकार नहीं दिखा रही गंभीरता

नई दिल्ली एजेंसी । भाजपा ने बुधवार को राज्यसभा में आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर हमलों का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से इस संबंध में उचित कार्रवाई का आग्रह किया। भाजपा सदस्य जीवीएल नरसिम्हा राव ने उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए दावा किया कि पिछले 19 महीनों में आंध्र प्रदेश में हिन्दू मंदिरों पर हमले, उन्हें तोड़ने व मूर्तियों को अपवित्र करने और इसी प्रकार के अपराधों से संबंधित 140 मामले सामने आए हैं।

विभिन्न मंदिरों पर हुए हमलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वाईएसआर कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने इन मामलों के आरोपियों पर ठोस कार्रवाई के प्रति अभी तक ना तो कोई गंभीरता दिखाई है और ना ही कोई संवेदनशीलता। राव ने कहा, लोगों की भारी नाराजगी के बाद राज्य सरकार ने आधे-अधूरे मन से इन मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। राज्य पुलिस वास्तविक दोषियों को गिरफ्तार करने की बजाय उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है जिन्होंने ऐसी घटनाओं की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किए। अभी तक दोषी लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से आग्रह किया कि वह राज्य सरकार को अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए निर्देशित करे और इस सिलसिले में की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगे।

राजस्थान के जयपुर में एक ही डिजाइन के दफ्तर बनाएगी कांग्रेस, बंसल व माकन ने सीएम और डोटासरा से चर्चा की

जयपुर । भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस ने प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक पार्टी दफ्तरों के लिए खुद के भवन बनाने का निर्णय लिया है। जयपुर में बनने वाले पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से लेकर जिला व ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के दफ्तर एक ही डिजाइन के बनाए जाएंगे। पार्टी दफ्तरों के लिए खुद के भवन बनाने को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन कुमार बंसल व राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ चर्चा की। दोनों नेताओं ने पार्टी दफ्तरों के लिए बनाए जाने वाले एक्शन प्लॉन को लेकर गहलोत व डोटासरा से चर्चा की। बुधवार को माकन ने इस संबंध में प्रत्येक जिले की रिपोर्ट पर चर्चा की बंसल का कहना है कि प्रदेशभर में पार्टी की खुद की जमीनों का ब्यौरा तैयार कराया गया है। जहां पार्टी की खुद की जमीन है वहां शीघ्र निर्माण कार्य शुरू होगा और जहां खरीदनी है अथवा सरकार से आवंटित करानी है, उसको लेकर प्रक्रिया शुरू की जाएगी, उन्होंने कहा कि सभी दफ्तर एक ही डिजाइन के होंगे। बुधवार सुबह माकन के साथ चर्चा के बाद डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों के लिए जमीन आवंटन नीति तैयार करने में जुटी है। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वायत्त शासनमंत्री शांति धारीवाल को जिम्मा सौंपा है। उम्मीद है अगले माह तक सरकार इस संबंध में नीति बना लेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी दफ्तरों का निर्माण खुद के कोष से होगा। उल्लेखनीय है कि जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय शहर के पुराने इलाके में करीब 100 साल पुराने भवन में चल रहा है। जयपुर शहर जिला कांग्रेस के दफ्तर भी किराये के भवनों में चल रहे हैं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में किराये के भवनों में दफ्तर चल रहे हैं। गहलोत ने जिलों के प्रभारी मंत्रियों को दफ्तर बनाने के काम में समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी है।

महाराष्ट्र में 94 पक्षी मिले मृत, अब तक 20,017 पक्षियों की हो चुकी है बर्ड फ्लू से मौत

मुंबई । महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू के संक्रमण के बीच 94 पक्षी मृत पाये गए हैं। राज्य में 8 जनवरी से पक्षियों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ था। यहां अब तक 20,017 पक्षियों की बर्ड फ्लू के कारण मौत हो चुकी है। हालांकि बीते आठ दिन के आंकड़े देखे जाये तो पक्षियों की मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई है। एक अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को यहां 94 पक्षियों की मौत हुई थी। इन पक्षियों के नमूने जांच के लिए भेजे दिए गए हैं। पक्षियों के नमूनों को जांच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, भोपाल और रोग जांच अनुभाग, पुणे भेजे गए थे। मृत पाये गए पक्षियों में 63 पॉल्ट्री पक्षी, 25 कौवे, तोते और अन?य पक्षी शामिल थे। ठाणे, महापे और घनसोली से मरे हुए पॉल्ट्री पक्षियों के नमूने भी जांच के लिए भेजे गए थे उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। गौरतलब है कि जनवरी माह में बर्ड फ्लू की दस?तक के साथ ही दहशत फैल गई थी। मराठवाड़ा के परभणी और बीड के दो गांव से मृत पायी गए मुर्गियों के नमूनों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। जिसके बाद प्रशासन ने 2 हजार मुर्गियों को मारने का आदेश दिया था। मराठवाड़ा के परभणी जिले की सेलू तहसील के कुपता गांव ओर बीड जिले के लोखंडी सावरगाव से भी मृत मुर्गियों के नमूने ले जांच के लिए भेजे गए थे। इनकी जांच रिपोर्ट में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार कुपता में 468 पक्षियों को मारने के आदेश दिये गए थे जबकि लोखंडी सावरगांव में करीब 1600 पक्षियों को मारने के निर्देश दिए थे। महाराष्ट्र में अब तक 3 हजार 949 पक्षियों को मारा जा चुका है।

गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ टिकटों की मारामारी, कांग्रेस के घोषित उम्मीदवारों का विरोध

अहमदाबाद । गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों में टिकटों की मारामारी शुरू हो गई है। कांग्रेस में सूरत अहमदाबाद में पार्टी के घोषित प्रत्याशियों का विरोध होने लगा है वही कांग्रेस में महानगरपालिका के टिकट बेचे जाने का भी आरोप लग रहा है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव सातव निकाय चुनाव को लेकर गुजरात में डेरा जमाए हुए हैं तथा कांग्रेस नेताओं के साथ निजी फार्म हाउस पर पार्टी की बैठकें कर पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रहे हैं। अहमदाबाद तथा सूरत में कांग्रेस के घोषित उम्मीदवारों का विरोध भी शुरू हो गया है।

बताया जा रहा है कि अहमदाबाद से कांग्रेस विधायक हिम्मत सिंह पटेल, विधायक शैलेश परमार, विधायक ग्यासुद्दीन शेख, विधायक इमरान खेड़ावाला सहित कई बड़े नेता अपने करीबियों को टिकट दिलाने का दबाव बना रहे हैं। उनके विरोधी गुट महानगरपालिका के पूर्व नेता विपक्ष दिनेश शर्मा के समर्थक पार्टी के घोषित प्रत्याशियों का विरोध भी करने लगे हैं। एनएसयूआई तथा युवक कांग्रेस के नेता अमित राजपूत के नाम से इंटरनेट मीडिया पर एक पत्र भी वायरल हुआ है जिसमें कांग्रेस के टिकट दो से 8 लाख रुपए में बेचे जाने का आरोप लग रहा है। हालांकि राजपूत ने मीडिया के समक्ष आकर अपने नाम से वायरल पत्र से किसी तरह का संबंध होने से इनकार किया। राजपूत ने इस पत्र के वायरल होने की जांच की मांग भी की है। कांग्रेस मंगलवार शाम को बचते बचाते अहमदाबाद के 38 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी इससे पहले सूरत वडोदरा राजकोट जामनगर तथा भावनगर के करीब सवा सौ उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी। सूरत में वार्ड 17 से घोषित कांग्रेस के उम्मीदवार धीरू लाठिया का विरोध शुरू हो गया। वडोदरा में वार्ड 1 से उम्मीदवार अमी राजपूत को लेकर भी कांग्रेस का एक धड़ा नाराज है। कांग्रेस में टिकटों की मारामारी के चलते प्रदेश आलाकमान भी चिंता में है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मनीष दोषी का कहना है कि कांग्रेस को बदनाम करने के लिए भाजपा की ओर से इस तरह का पत्र वायरल किया गया है। भाजपा का आईटी सेल हर चुनाव से पहले कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकतें करता है। दोषी का यह भी कहना है कि कुछ लोग अपनी महत्वाकांक्षा तथा येन केन प्रकारेण टिकट पाने की लालसा में विरोधी पार्टी का मोहरा बन जाते हैं। उधर राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर ऐसी चर्चा शुरू हो गई है की हर चुनाव में कांग्रेस में टिकट वितरण में अनियमितता अथवा धांधली के आरोप क्यों लगते हैं। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के तहत 21 फरवरी को छह महानगरपालिका के लिए मतदान होना है। इसके बाद 31 जिला पंचायत तथा 131 तहसील पंचायतों के चुनाव होने हैं। करीब आठ एक नगर पालिकाओं के चुनाव भी इन्हीं के साथ होंगे। चर्चा है कि कांग्रेस को अपने पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते बैठक का स्थल भी बदलना पड़ रहा है।

राज्यसभा में हंगामा कर रहे आप के तीनों सांसद निष्कासित, लगा रहे थे कृषि कानूनों को रद्द करो के नारे

नई दिल्ली एजेंसी । किसानों के मुद्दे को लेकर रायसभा में भारी हंगामा कर रहे आम आदमी पार्टी के तीनों सांसद संजय सिंह, सुशील कुमार गुप्ता और एन.डी. गुप्ता को बुधवार को दिन भर के लिए निष्कासित कर दिया गया। सभापति एम. वेंकैया नायडू ने शून्यकाल काल के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कराने का प्रयास किया तो आप के तीनों सांसद अपनी सीटों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। उन्होंने कृषि कानूनों को रद्द करो के नारे लगाए।

वैंकैया नायडू ने कहा कि अभिभाषण पर चर्चा के दौरान ही किसानों के मुद्दे पर बहस करने की सहमति बन चुकी है। ऐसे में इन सदस्यों का सदन की कार्यवाही को बाधित करना अनुचित है। ये लोग वास्तव में किसानों के मुद्दे पर चचा नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने तीनों सदस्यों से शांत होने और सदन की कार्यवाही चलने देने का अनुरोध किया, लेकिन इस पर भी तीनों सांसद नारे लगाते रहे।

इसके बाद उन्होंने तीनों सांसदों को नियम 255 के तहत सदन की कार्यवाही से बाहर करने की चेतावनी दी लेकिन सदस्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे नारे लगाते रहे। इस पर सभापति ने कहा कि इन तीनों सदस्यों को सदन की कार्यवाही से दिनभर के लिए बाहर कर रहे हैं और उन्होंने तीनों सदस्यों को दिन भर के लिए सदन से बाहर जाने का आदेश दिया और सदन की कार्यवाही 9:30 बजे पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी।

संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और किसानों के मुद्दे पर आज भी हंगामा के आसार नजर आ रहे हैं। रायसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। आज एक बार फिर से संसद में किसान आंदोलन और कृषि कानूनों पर घमसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद ने 19 पार्टियों की ओर से किसानों के मुद्दे पर चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा। वहीं, संसद के दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 फरवरी को रायसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा का जवाब देंगे।

किसानों के आंदोलन और उनसे जुड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार और विपक्ष में सहमति बन गई है। सरकार और विपक्ष में बनी सहमति के मुताबिक, रायसभा में किसानों के मुद्दे पर 15 घंटे तक चर्चा होगी।

मां की मौत के बाद 15 साल की लड़की का 17 लोगों ने 5 महीने तक किया रेप, रिश्तेदार सहित 8 गिरफ्तार

बेंगलुरु । कर्नाटक के चिक्कमंगलुरु जिले में मानवता और रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मासूम का एक नहीं बल्कि कई लोगों ने महीनों तक रेप किया। उसे इस दलदल में धकेलने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका रिश्तेदार ही था। पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई और गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ।

पांच महीने तक 15 साल की एक लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि नौ अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शृंगेरी पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें लड़की की एक रिश्तेदार भी शामिल है, जिसने उसे वेश्यावृत्ति में धकेल दिया था। अधिकारी ने बताया, 'हमने उसकी रिश्तेदार (चिक्कम्मा) सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसने उसे वेश्यावृत्ति में धकेल दिया था। लड़की का यौन शोषण करने वाले नौ अन्य लोगों की तलाश जारी है।'

पुलिस के अनुसार, तीन साल पहले अपनी मां की मौत के बाद लड़की अपनी चिक्कम्मा के साथ रहने लगी। पिछले कुछ महीनों से वह एक स्टोन क्रशिंग इकाई में काम कर रही थी और एक बस चालक के संपर्क में आई जिसने उसका कथित रूप से यौन शोषण किया।

पुलिस ने बताया कि बाद में, उसने और उसके साथियों ने उसके साथ बलात्कार किया, वीडियो बनाए और उसे ब्लैकमेल किया। उन्होंने बताया कि उसकी चिक्कम्मा को इसके बारे में पता था, फिर उसने यह सब होने दिया। पुलिस ने बताया कि आईपीसी की विभिन्न धाराओं, बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम व कई अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

कोविड-19: कोरोना के उबरने लगा भारत, 24 घंटों में सामने आए 11,039 नए मामले

नई दिल्ली एजेंसी । लंबे समय से कोरोना का कहर झेल रहे भारत को वैक्सीन आने के बाद से राहत मिलती दिख रही है। दैनिक आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पिछले 24 घंटों में भारत में 11,039 नए कोविड??-19 मामले सामने आए है और 14,225 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके है। वहीं 110 लोगों की मौतें हुई हैं। इसके अलावा अब तक के कुल मामलों की बात करें तो ये 1,07,77,284 है। 1,04,62,631 लोग पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। सक्रिय मामले 1,60,057 पर हैं जबकि 1,54,596 लोग जान गवां चुके हैं। वहीं कुल 41,38,918 लोगों का टीकाकरण किया गया है।

मंत्रालय ने बताया कि 29 जनवरी तक देश में लोगों को टीके की खुराकें देने के मामले में भारत पांचवें स्थान पर है। मंत्रालय ने बताया कि 31 राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में उपचाराधीन मामलों की संख्या 5000 से कम है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में उपचाराधीन मामलों की संख्या चार है, वहीं दमन और द्वीव तथा दादर और नगर हवेली में छह है। कोविड-19 के 79.69 प्रतिशत उपचाराधीन मामले पांच राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों से हैं। मंत्रालय ने कहा, दो राज्यों केरल और महाराष्ट्र में देश के कुल उपचाराधीन मामलों के 69.41 प्रतिशत मामले हैं।

पश्चिम बंगाल समैबे समिति के सदस्य कोलकाता में अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग करते हुए एक विरोध प्रदर्शन करते हुए नकदी इकट्ठा करते हुए।

नागपुर के सरकारी अस्पताल के वार्ड में घूमते दिखे आवारा कुत्ते, वीडियो वायरल

नागपुर । महाराष्ट्र के नागपुर में प्रशासन की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) में मरीजों के वार्ड के अंदर आवारा कुत्तों का वीडियो वायरल हो गया है। जीएमसी नागपुर के अधीक्षक ने कहा, ÷ जो कथित वीडियो में सामने आया है हम उसके तथ्यों की जांच कर रहे हैं, इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ये आवारा कुत्ते अस्पताल के किसी भी वार्ड में घुस जाते हैं और वहां मरीजों के थैलों में खाने का सामना ढूंढते रहते हैं।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के कापसिकोपरी गांव से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया था। यवतमाल के इस गांव में 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर के ड्रॉप पिला दी गई थी। इन सभी बच्चों की उम्र 1 से 5 वर्ष के बीच बतायी गई है। मामला तब सामने आया जब डॉप देते ही बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। डॉप लेते ही बच्चों को उल्टी और बैचेनी की शिकायत होने लगी।

मिलिए कश्मीर की आयशा अजीज से, जिन्होंने देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर रच दिया इतिहास

नई दिल्ली एजेंसी । आज के वक्त में किसी भी काम में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं और इस बात को एक बार फिर से साबित किया है जम्मू-कश्मीर की रहने वालीं 25 साल की आयशा अजीज ने। कश्मीर से आने वालीं आयशा अजीज ने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पालयट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। जी हां, कश्मीर की रहने वाली आयशा अजीज सबसे कम उम्र में देश की महिला पायलट बन गई हैं। आयशा का यह कारनामा न सिर्फ प्रेरणा स्रोत है, बल्कि कश्मीरी महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का प्रतीक भी है।

2011 में महज 16 साल की उम्र में ही लाइसेंस पाने के बाद आयशा स्टूडेंट पायलट बनी थीं। उसके अगले साल उन्होंने रूस के सोकोल एयरबेस में MIG-29 जेट उड़ाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया। आयशा जब 16 साल की थी तब से स्कूल में ही ट्रेनिंग लेने लगी थीं और साल 2017 में बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से उन्हें कमर्शियल लाइसेंस मिल गया था।

आयशा अजीज ने कहा कि उनका मानना है कि कश्मीरी महिलाओं ने पिछले कुछ वर्षों में काफी प्रगति की है और शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण रूप से अच्छा किया है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि कश्मीरी महिलाएं अच्छा कर रही हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। कश्मीर की हर दूसरी महिला अपने परास्नातक या डॉक्टरेट कर रही है। घाटी के लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं।

उन्होंने बताया,मुझे हवाई यात्रा करना और लोगों से मिलना अच्छा लगता है। इस वजह से मैंने पायलट बनने का निर्णय लिया। पायलट बनने के लिए आपका मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने आगे कहा कि इस पेशे में किसी की मानसिक स्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए क्योंकि 200 यात्रियों को ले जाना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है।

उन्होंने कहा कि मैंने इस क्षेत्र को इसलिए चुना क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र से यात्रा करना पसंद करती थी और र उड़ान मुझे काफी रोमांचित करता है। एक व्यक्ति को इतने सारे लोग मिलते हैं। यही कारण है कि मैं एक पायलट बनना चाहती थी। यह काफी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यह 9 से 5 बजे वाली डेस्क जॉब नहीं है। इसमें कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं है और मुझे लगातार नए स्थानों, विभिन्न प्रकार के मौसम का सामना करने और नए लोगों से मिलने के लिए तैयार रहना होता है। आयशा ऐसा करने वाली तीन भारतीयों में से एक हैं। आयशा की मां जम्मू कश्मीर के बारामुला जिले की रहने वाली हैं। उनके पिता महाराष्ट्र के मुंबई से हैं। आयशा के भाई का कहना है कि उनकी बहन ने कश्मीरी लड़कियों के लिए एक मिसाल कायम की है।

ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा की जांच में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- सरकार के पास जाएं

नई दिल्ली एजेंसी । सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट याचिकाकर्ताओं को सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व दर्ज कराने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि शीर्ष अदालय में दायर एक याचिका में घटना की जांच के लिए शीर्ष अदालत के रिटायर जज की अध्यक्षता में आयोग बनाने का भी अनुरोध किया गया था।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि हमें यकीन है कि सरकार इसकी जांच कर उचित कार्रवाई कर रही है। पीठ ने आगे कहा कि हमने प्रधानमंत्री के बयान को अखबारों में पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। इसका मतलब है कि सरकार पूछताछ कर रही है।

केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के पक्ष में 26 जनवरी को हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली थी, लेकिन कुछ ही देर में दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैल गई। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के अवरोधकों को तोड़ दिया और पुलिस के साथ भी उनकी झड़प हुई। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने वाहनों में तोड़ फोड़ की और लाल किले पर एक धार्मिक ध्वज लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन की पीठ इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई की।

अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दाखिल याचिका में शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच आयोग गठित करने का अनुरोध किया गया था, जिसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तीन सदस्यीय इस आयोग में उच्च न्यायालय के दो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को शामिल करने का आग्रह किया गया था। याचिका में 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के लिए जिम्मेदार लोगों अथवा संगठनों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के वास्ते संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया था।

उदयपुर के राजसमंद में घूस लेते कम्प्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार

उदयपुर । भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर की टीम ने राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपकोष कार्यालय में संविदा पर सेवारत कम्प्यूटर ऑपरेटर को पांच हजार रुपए की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। उसने यह राशि पेंशन एरियर का बिल पास करने के एवज में ली थी। विभाग ने कार्रवाई करते हुए उसकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। मिली जानकारी के अनुसार कम्प्यूटर ऑपरेटर मुकेश दास वैष्णव पिछले चार साल से कुंभलगढ़ स्थित उप कोष कार्यालय में संविदा पर सेवारत था। वह इस कार्यालय में वृद्धावस्था पेंशन योजना का काम देखता है। इस मामले में उप कोष अधिकारी भानुप्रकाश साहू की लिप्तता को लेकर भी जांच की जा रही है। उनके दोषी पाए जाने पर एसीबी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। बताया गया कि कुंभलगढ़ निवासी जवाहर लाल ने उदयपुर एसीबी कार्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर की शिकायत की थी। जिसमें उसने बताया कि उनका पेंशन का केस 27 जुलाई 2020 को स्वीकृत होकर उपकोष कार्यालय कुंभलगढ़ में प्राप्त हुआ। कार्यालय में पेंशन का काम देखने वाला कर्मचारी मुकेश दास वैष्णव पेंशन का बिल पास करवाने की एवज में उपकोष अधिकारी के नाम से 5 हजार रुपए की घूस मांग रहा था।

आरोपी मुकेश दास उपकोष कार्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर का काम करता है और ऑनलाइन प्राप्त होने वाले आवेदनों को कोषाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है। उसने रिश्वत राशि लेकर जवाहर लाल को अपने कार्यालय बुलाया। जहां उसके घूस लेते समय तत्काल उसे दबोच लिया। एसीबी टीम नेउसकी जेब से रिश्वत की राशि बरामद की। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने उप कोष अधिकारी के कहने पर ही रिश्वत राशि ली। इस मामले में एसीबी ने मुख्यालय से उप कोष अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति मांगी है। इधर, विभाग ने संविदा पर सेवारत कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर उदयपुर लाया गया है, जहां विशिष्ट न्यायालय में उसे पेश किया जाएगा।

जोधपुर में जनजाति उत्थान के लिए सरकार की पहल, मारवाड़ क्षेत्रीय माडा का गठन

जोधपुर । जोधपुर संभाग के माडा, माडा क्लस्टर एवं बिखरी जनजाति क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति समुदाय के सर्वतोमुखी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विशेष योजना निर्माण और सफल क्रियान्वयन के लिए मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड (माडा) का गठन किया गया है। इस बोर्ड का मुख्यालय जोधपुर होगा। यह बोर्ड जोधपुर के अनुसूचित जनजाति समुदाय के सर्वतोमुखी उत्थान एवं विकास के विषय में राज्य सरकार की स्थायी परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करना सुनिश्चित करेगा तथा इस संबंध में विशेष योजनाओं का निर्माण कर उन्हें जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग व अन्य विभागों के माध्यम से क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार को संस्तुति प्रदान करेगा। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुनसिंह बामनिया ने जैसलमेर में यह जानकारी देते हुए बताया कि इस बोर्ड में प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है। इसी प्रकार संभागीय आयुक्त, जोधपुर को सदस्य सचिव के रूप में मनोनीत किया गया है। इसके साथ ही गठित किये बोर्ड में जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, सिरोही तथा जैसलमेर जिले के जिला कलक्टरों को पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जबकि इन जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद-सह-मुख्य परियोजना अधिकारी, माडा बोर्ड में पदेन सचिव रहेंगे।

अतिरिक्त आयुक्त (चतुर्थ) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (माडा) जोधपुर को पदेन सदस्य तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत संभाग के प्रत्येक जिले से अनुसूचित जनजाति समुदाय का एक- एक प्रतिष्ठित व्यक्ति (कुल छह व्यक्ति) सदस्य के रूप में मनोनीत किये गये हैं।बोर्ड द्वारा आवश्यकतानुसार विभिन्न संभागीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को स्थायी अथवा विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में अपनी बैठकों में आमंत्रित किया जा सकेगा तथा अपने कार्य संचालन में उनका अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को प्रतिवर्ष बजट राशि उपलब्ध करायी जाएगी जिसके संदर्भ में सदस्य सचिव द्वारा कार्ययोजना तैयार की जाकर बोर्ड से अनुमोदन करवाया जाएगा व आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को भेज दिया जाएगा। इसी क्रम में आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग इस कार्ययोजना पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर विभिन्न विभागों के सहयोग से क्रियान्वित कराने के लिए उत्तरादायी होंगे।बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये गये सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा तथा बोर्ड का अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में इस पद का कार्यवहन संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा संपादित किया जाएगा।

बैंक से 15 लाख रुपये के सिक्के गायब: ऑडिट में सामने आयी हेराफेरी, शिकायत दर्ज

भुवनेश्वर । ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पिछले चार साल में 15 लाख रुपये के सिक्के गायब हो चुके हैं।। बैंक में चल रहे आंतरिक अडिट के समय इस हेराफेरी के बारे में पता चली है। इस संबंध में बैंक के चार कर्मचारियों के नाम पर आरोप सामने आने के बाद पुलिस छानबीन शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक वर्ष 2016 से 2020 के बीच पारादीप गड़ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 14 लाख 86 हजार 780 रुपये के सिक्के गायब हुए थे उक्त समय यह बैंक कार्पोरेशन बैंक के नाम से संचालित हो रहा था। एक सप्ताह पहले नए सिरे से योगदान देने वाले बैंक मैनेजर ने जब दायित्व संभालने के बाद इस धांधली की छानबीन शुरू हुई। बैंक में चल रही आंतरिक अडिट के समय इस तरह की हेराफेरी होने की बात बता चलने के बाद बैंक मैनेजर ने पारादीप थाना में चार लोगों के नाम पर शिकायत दर्ज करायी है। इस हेराफेरी में बैंक के ही किसी पूर्व कर्मचारी के शामिल होने का संदेह किया जा रहा है।

बैंक के मैनेजर ने कहा है कि अडिट के समय यह हेराफेरी पकड़े जाने की बात पता चलते ही बैंक मुख्यालय को इसकी जानकारी दे दी गई है और इस संबंध में थाने में लिखित शिकायत कर दी गई है।

तापसी पन्नू ने बॉलीवुड में भेदभाव को लेकर बयां किया दर्द, कहा- मुझसे फीस कम करवाई जाती थी

तापसी पन्नू (Tapsee Pannu) सिर्फ अपने दमदार रोल और एक्टिंग ही नहीं रियल लाइफ में भी अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में तापसी ने बॉलीवुड (Bollywood) में भेदभाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. तापसी ने उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि हीरो की पिछली फिल्म फ्लॉप होने पर मुझे अपनी फीस कम करने को कहा जाता था, जिससे फिल्म का बजट कंट्रोल किया जा सके. तापसी ने कहा, 'अपने करियर के शुरुआती दौर में मुझे इंडस्ट्री में कई बुरे एक्सपीरियंस देखने पड़े. जैसे कि मुझे कई बार इसलिए रिप्लेस कर दिया जाता था, क्योंकि मैं बॉलीवुड की ज्यादातर हीरोइन की तरह सुंदर नहीं थी.

तापसी ने एक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि एक फिल्म के लिए डबिंग करने के समय मुझसे कहा गया कि हीरो को मेरे डायलॉग पसंद नहीं आ रहे हैं, इसलिए इसे बदलना पड़ेगा. मेरे मना करने पर दूसरे डबिंग आर्टिस्ट से वो काम करा लिया गया. अपने हाल ही में दिए इंटरव्यू में तापसी ने आगे कहा, कुछ एक्टर्स तो ऐसे भी थे जिन्हें लगने लगा था कि कहीं मेरे सीन्स उनके इंट्रोडक्शन सीन्स पर भारी ना पड़ जाएं. इसलिए वो चाहते थे कि मेरा इंट्रोडक्शन सीन बदल दिया जाए या कभी किसी एक्टर की वाइफ नहीं चाहती थी कि मैं फिल्म का हिस्सा बनूं.

शाबाश मिथुकी तैयारियों में जुटीं तापसी ने बॉलीवुड में भेदभाव को लेकर कहा कि मुझे इतना ही पता है लेकिन इसके अलावा क्या पता इंडस्ट्री में मेरे पीछे क्या-क्या होता है. इसके बाद से ही मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं उन फिल्मों में ही काम करूंगी, जिसमें काम कर मुझे अच्छा महसूस हो. वर्कफ्रंट की बात करें तो तापसी पन्नू ने कुछ दिनों पहले ही अपनी अपकमिंग फिल्म 'रश्मि रॉकेट' की शूटिंग पूरी की है. अब वो क्रिकेटर मिताली राज की बायोपिक 'शाबाश मिथु' की तैयारियों में बिजी हैं. इस फिल्म के लिए वो कोच नूशीन अल खदीर से क्रिकेट की ट्रेनिंग भी ले रही हैं. तापसी ने हाल ही में ट्रेनिंग लेते हुए एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया था. यह फिल्म राहुल ढोलकिया के निर्देशन में बन रही है.

कंगना रनौत ने ट्विटर इस्तेमाल करने की बताई अनोखी वजह, वायरल हुआ TWEET

एक्ट्रेस कंगना रनौत को अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्विटर' की आलोचना करते हुए देखा गया है. फिर भी ट्विटर इस्तेमाल करने की उन्होंने अनोखी वजह बताई. कंगना ने बताया कि वह अपनी सेल्फ-रिस्पेक्ट दांव पर लगाकर इसलिए ट्विटर इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि वह देशभक्त हैं.

एक ट्विटर यूजर ने एक आर्टिकल शेयर किया था, जिसमें बताया गया था कि डिप्लोमैटिक संबंधों के खातिर भारत पाकिस्तान को कोविड-19 वैक्सीन पहुंचा रहा है. कंगना ने इस ट्वीट को कोट करते हुए लिखा, 'और इसलिए हम जैसे लोग अपना आत्मसम्मान गिरवी रखकर इस बेहूदा, भद्दे और कम्युनिष्ट प्लेटफॉर्म 'ट्विटर' पर टिके हुए हैं. वे नहीं बताएंगे और अगर हम नहीं बताएंगे, तो कौन बताएगा? देश से बढ़कर कुछ नहीं...जय हिंद.'बीते माह कंगना ने उनके अकाउंट को अस्थायी रूप से बंद करने की वजह से ट्विटर की काफी आलोचना की थी. ट्विटर ने यह कदम उनके उस पोस्ट की वजह से उठाया था, जिसमें उन्होंने अमेजन प्राइम वीडियो की सीरीज 'तांडव' (Tandav) के खिलाफ बोला था. उन्होंने उस कमेंट में कहा था कि धार्मिक भावनाएं आहत करने के जुर्म में निर्माताओं का सर कलम करना चाहिए.

ट्विटर सीईओ और को-फाउंडर जैक डोर्सी को टैग करते हुए कंगना रनौत ने लिखा था, 'चाचाञ्चजैक अपने मूर्ख प्रतिनिधियों को बताएं कि 'हेड ऑफ' एक मुहावरा है, जिसका मतलब धमकाना है. उम्मीद है कि आप उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे जो रोजाना प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, साधु और ब्राहमणों को असली मं धमकाते हैं और उनकी मृत्यु की कामना करते हैं. झूठे बेशर्म.'

इससे पहले कंगना ने आरोप लगाया था कि लिब्रल्स जैक से जाकर रोए थे और उनके अकाउंट पर अस्थायी रोक लगवाई थी. एक ट्वीट में वह कहती हैं कि अगर उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उनका 'देशभक्त' स्वरूप उनकी फिल्मों में दिखाई देगा. वह अपने आलोचकों को धमकाती हैं कि वह उनकी जिंदगी नर्क बना देंगी.

राहुल वैद्य का गर्लफ्रेंड दिशा के साथ Dance Video वायरल, फैंस पूछ रहे अजीब सवाल

सिंगर राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) बिग बॉस (Bigg Boss) के घर में कंटेस्टेंट बन कर आए और उसके बाद इस शो में ही उन्होंने खुले आम अपनी दोस्त दिशा परमार (Disha Parmar) से प्यार का इजहार भी किया. घर में मां आईं तो उन्होंने दोनों की शादी के बारे में भी बात की. इसी बीच राहुल के एक फैन क्लब ने दिशा और राहुल का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दोनों डांस करते दिख रहे हैं. वीडियो देखकर लग रहा है कि दोनों किसी शादी के फंक्शन में डांस कर रहे हैं. वीडियो के सामने आते ही राहुल के फैंस तो उनकी तारीफ कर रहे हैं लेकिन कुछ यूजर उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं.

इस वीडियो में राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) और दिशा परमार (Disha Parmar) 'दिल चोरी साड्डा हो गया गाने पर डांस कर रहा है. यह वीडियो किसी फंक्शन का है लेकिन ये किस इवेंट या शादी का है. या फिर कब और किसके फंक्शन का है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. वीडियो शेयर होने के बाद काफी वायरल हो रहा है. इसे फैन क्लब राहुल नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. वीडियो में जहां राहुल ने नीले रंग का कुर्ता और सफेद रंग का पायजामा पहना है. वहीं दिशा परमार भी ट्रेडिशनल ड्रेस में दिख रही हैं.

राहुल के फैंस तो उन्हें देखकर खुश हैं लेकिन वहीं कुछ यूजर उनसे अजीब सवाल भी पूछ रहे हैं. एक यूजर का कहना था कि जब आपकी गर्लफ्रेंड है तो फिर वो क्यों घर के अंदर निक्की से फलर्ट करते हैं. वहीं एक यूजर ने पूछा कि जब ये दोनों कपल हैं तो फिर घर के अंदर प्रपोज़ल का ड्रामा क्यों किया. बता दें कि राहुल ने घर के अंदर से अपनी दोस्त दिशा को शादी का प्रस्ताव दिया था. घर के अंदर इनदिनों राहुल और अली गोनी की दोस्ती के चर्चे हैं. इन दोनों को दर्शक भी खूब पसंद कर रहे हैं. राहुल जब इस शो को छोड़कर गए थे तो फैंस उनसे गुस्सा हो गए थे. बाद में राहुल ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली और उसके बाद उन्हें घरवालों के ताने भी सुनने पड़े थे.

रकुलप्रीत सिंह बनीं आयुष्मान खुराना की हीरोइन, फिल्म 'डॉक्टर जी' में मिली एंट्री

जंगली पिक्चर्स' (Junglee Pictures) ने आयुष्मान खुराना (Ayushman Khurana) के साथ दूसरी बार फिल्म 'डॉक्टर जी' (Doctor G) बनाने का फैसला किया है. इसकी घोषणा बीते दिसंबर में कर दी गई थी. इस फिल्म को अनुभूति कश्यप, (Anubhuti Kashyap) निर्देशित कर रही हैं. निर्माता निर्देशक ने इस फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) को लेने का फैसला किया है.

इस फिल्म में रकुल प्रीत सिंह एक मेडिकल छात्रा डॉक्टर फातिमा का किरदार निभाएंगी. इस फिल्म में आयुष्मान डॉक्टर उदय की भूमिका में हैं. रकुल उनके कॉलेज की सीनीयर छात्रा हैं. इस फिल्म का हिस्सा बनकर रकुलप्रीत सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं है.उन्होंने टाइम्स से बता करते हुए कहा कि 'मैं सुपर एक्साइटेड हूं, कई चीजें हैं जो इस फिल्म के जरिए पहली बार हो रही है, जैसे आयुष्मान खुराना के साथ काम करना. मैं 'जंगली पिक्चर्स' और डायरेक्टर अनुभूति कश्यप की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आयुष्मान के साथ काम करने का मौका दिया है. रकुल बताती हैं कि ये एक दिलचस्प स्टोरी है, इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनते ही मुझे काफी पसंद आई. ये फिल्म मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी और कॉलेज कैम्पस की कहानी है. दर्शकों को एक अलग तरह की कहानी देखने को मिलेगी. मैं बेसब्री से फिल्म की शूटिंग शुरु होने का इंतजार कर रही हूं.अनुभूति कश्यप बताती हैं कि ' दो अलग अलग तरह की शख्सियत के साथ काम करना बहुत ही मजेदार होता है. हम इस फिल्म के लिए कुछ अलग तरह के किरदार की तलाश में थे, और मुझे बहुत खुशी है कि रकुल और आयुष्मान इस फिल्म में हैं. मुझे उम्मीद है कि एनर्जी से भरी इन दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आएगी'.

'जंगली पिक्चर्स' की सीईओ अमृता पांडेय ने बताया है कि ' इस फिल्म की कहानी मेरे दिल के काफी करीब है, और इस फिल्म के लीड रोल में रकुल को लेकर हम बहुत उत्साहित है. रकुल ने अपनी एक्टिंग से भारतीय दर्शकों के बीच अपनी खास जगह बनाई है. इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरु होगी. फिल्म 'डॉक्टर जी' के अलावा रकुलप्रीत सिंह अजय देवगन और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'मे डे' में काम कर रही हैं. साथ ही सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ 'थैंक गॉड' की शूटिंग भी कर रही हैं.'जंगली पिक्चर्स' की सीईओ अमृता पांडेय ने बताया है कि ' इस फिल्म की कहानी मेरे दिल के काफी करीब है, और इस फिल्म के लीड रोल में रकुल को लेकर हम बहुत उत्साहित है. रकुल ने अपनी एक्टिंग से भारतीय दर्शकों के बीच अपनी खास जगह बनाई है. इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरु होगी. फिल्म 'डॉक्टर जी' के अलावा रकुलप्रीत सिंह अजय देवगन और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'मे डे' में काम कर रही हैं. साथ ही सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ 'थैंक गॉड' की शूटिंग भी कर रही हैं.

पहले टेस्ट के लिए टीम इंडिया के अंतिम ग्यारह में इन खिलाड़ियों का शामिल होना तय

चेन्नई, (एजेंसी)। इंग्लैंड के साथ शुक्रवार से शुरू हो रही चार टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया के अंतिम ग्यारह खिलाड़ियों का चयन आसान नहीं रहेगा। इस सीरीज से विराट कोहली एक बार फिर कप्तानी की कमान संभालंगे। वहीं अजिंक्य रहाणे उप-कप्तानी करेंगे। पहले दो टेस्ट मैच चेन्नई में खेले जाएंगे, जिसकी पिच स्पिनरों की सहायक रही है, ऐसे में भारतीय टीम के तीन स्पिनरों के साथ उतरने की संभावना है।

ऑस्ट्रेलिया दौरे में युवाओं ने शानदार प्रदर्शन किया था ऐसे में अब अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी के करण टीम इंडिया के लिए अंतिम ग्यारह खिलाड़ियों का चयन मुश्किल हो गया है।

पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल का उतरना तय माना जा रहा है। ये दोनों ही बल्लेबाज काफी तेजी से रन बनाने में सक्षम हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी ये जोड़ी सफल रही थी। रोहित घरेलू मैदानों पर और भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं।

वहीं तीसरे नंबर पर भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का उतारा जाएगा।

इसका कारण है कि पुजारा फॉर्म में भी है। पुजारा ने ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। सिडनी टेस्ट में पुजारा ने 50 और 77 रनों की पारियां खेलीं, जबकि ब्रिस्बेन के निर्णायक टेस्ट मैच में उन्होंने दूसरी पारी में 56 रनों की पारी खेलकर टीम की सीरीज जीत में अहम योगदान दिया था। पुजारा कठिन हालातों में भी एक छोर पर जमे रहते हैं।

वहीं कप्तान विराट कोहली नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। विराट की वापससे भारतीय क्रिकेट टीम की ताकत और भी बढ़ जाएगी। विराट पहले टेस्ट मैच में मैच विजेता साबित हो सकते हैं। पिछले साल वह एक भी शतक नहीं बना पाये थे ऐसे में उनका लक्ष्य इंग्लैंड के खिलाफ अधिक से अधिक रन बनाना रहेगा।

इसके अलावा उप-कप्तान अजिंक्य रहाणे नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया कप्तानी के साथ ही शानदार बल्लेबाजी की थी। ऑस्ट्रेलिया में टीम को जीत दिलाने का यह सिलसिला वह अब भी जारी रखना चाहेंगे।

युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए छठे नंबर पर उतरेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में खेले गए निर्णायक टेस्ट मैच में नाबाद 89 रनों की पारी खेलकर भारत को ऐतिहासिक सीरीज जीत दिलाने वाले ऋषभ पर इस सभी की नजरें होंगी। ऋषभ ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर अपनी शानदार बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया था।

वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर के तौर पर नंबर 7 पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। वॉशिंगटन सुंदर ऑफ ब्रेक गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में भी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में खेले गए निर्णायक टेस्ट में सुंदर ने शानदार डेब्यू किया था और पहली पारी में 62 रनों की पारी खेलकर मैच को पलट दिया था। अव वह यही फार्म आगे भी जारी रखना चाहेंगे।

इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट मैच में स्पिन का दारोमदार अनुभवी आर अश्विन पर रहेगा। पहले दो टेस्ट मैच चेन्नई में खेले जाएंगे, जिसकी पिच स्पिनरों की सहायक रही है। चेन्नई अपने घरेलू मैदान पर और भी प्रभावी रहेंगे। वह यहां काफी क्रिकेट खेल चुके हैं।।ऐसे में इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए अश्विन का सामना आसान नहीं रहेगा।

वॉशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन के साथ ही कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव के आने से भी स्पिन विभाग की ताकत बढ़ेगी। कुलदीप एक साल के अंतराल के बाद इस मैच से वापसी करेंगे। ऐसे में उनका इरादा बेहतर प्रदर्शन करना रहेगा।

पेस बॉलिंग अटैक की कमान जसप्रीत बुमराह संभालेंगे। उनकी सहायता के लिए

दूसरे तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज या

अनुभवी ईशांत शर्मा को शामिल किया जा सकता है। भारत की संभावित अंतिम ग्यारह - रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज।

मेलबोर्न में ब्रिटेन की कैटी बोल्टर ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस के लिए अभ्यास करती हुईं।

दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव नहीं मानने से रद्द हुई सीरीज : हॉकले

सिडनी, (एजेंसी)। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) के अंतरिम सीईओ निक हॉकले ने दौरा नहीं होने के लिए क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) को ही जिम्मेदार बताया है।

हाकले ने कहा है कि उन्होंने टेस्ट सीरीज का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में करने का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीकी बोर्ड को दिया था पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इससे पहले दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने सीए द्वारा अगले महीने होने वाले दौरे के रद्द होने पर निराशा जताई थी। हॉकले ने कहा, हम क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हम आने वाले हफ्तों और महीनों में काम करेंगे जब हम सीरीज को फिर से तैयार करने में सक्षम हो सकते हैं। हमने इस सीरीज की मेजबानी करने की पेशकश की थी, लेकिन सीएसए ने यह स्पष्ट किया कि उन्हें कई अन्य प्रतिबद्धताएं भी मिली हैं और क्वारंटाइन अवधि के तहत यह संभव नहीं था।

उन्होंने आगे कहा, हमने बहुत अधिक विवरणों में तटस्थ स्थानों का पता नहीं लगाया, यदि आप एक तटस्थ स्थान के बारे में सोचते हैं तो सवाल यह है कि विभिन्न न्यायालयों में बहुत सारी चुनौतियां हैं, इसलिए निश्चित रूप से हमने मेजबान और सीएसए को औपचारिक प्रस्ताव दिया, जिसका हम पूरी तरह से सम्मान करते हैं। उनकी स्थिति बहुत स्पष्ट है और हमने इसे जारी रखने के लिए जितना संभव हो उतना कठिन काम करना जारी रखा है। लेकिन हम एक ऐसे बिंदु पर आ गए जहां लोग लागत कम करने लगे थे, लोग पूर्व-प्रस्थान प्रोटोकॉल करना शुरू कर रहे थे और तैयारी में दक्षिण अफ्रीका में जैव-सुरक्षित वातावरण में प्रवेश कर रहे थे।

उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमने खुद को हर मौका दिया, हम इसे बाद में नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन अंत में जो अवशिष्ट जोखिम था, निहितार्थ अगर हमें एक सकारात्मक मिला, सकारात्मक होने की संभावना है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास वास्तव में हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। वहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले पर निराशा व्यक्त करते हुए क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने कहा, हम सीए की हर एक अपेक्षा को पूरा करने के लिए हफ्तों में अथक प्रयास कर रहे थे।

फाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को चाहिये इंग्लैंड पर जीत

चेन्नई, (एजेंसी)। टीम इंडिया इंग्लैंड से सीरीज जीतने के बाद ही आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की दावेदार रहेगी। इस सीरीज के परिणाम से यह तय होगा कि टीम इंडिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचेगी या नहीं। वहीं ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण अफ्रीका दौरा स्थगित होने से न्यूजीलैंड की टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। न्यूजीलैंड के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 420 अंक हैं और उसका जीत प्रतिशत 70 है। न्यूजीलैंड को अब 18 जून को होने वाले फाइनल से पहले कोई टेस्ट सीरीज नहीं खेलनी है। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया 332 अंक तकरीबन 69.2 जीत प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं टीम इंडिया 71.7 जीत प्रतिशत अंक के साथ पहले नंबर पर है हालांकि अभी उसे इंग्लैंड से चार टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है।

न्यूजीलैंड ने तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है हालांकि दूसरी टीम के लिए अभी तीन दावेदार दौड़ में बने हैं। फाइनल में पहुंचने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मुकाबला होगा। अगर भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज ड्रॉ होती है तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच जाएगा।

वहीं भारत को अगर फाइनल में पहुंचना है तो उसे हर हाल में इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज में दो मैच तो जीतने ही होंगे। ड्रॉ, हार या 1-0 की जीत उसे इस दौड़ से बाहर कर सकती है। वहीं अगर भारत 2-1 से भी टेस्ट सीरीज जीतता है तो भी वो फाइनल में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इंग्लैंड 1-0, 2-0 या 2-1 से सीरीज जीत हासिल करता है तो ऑस्ट्रेलिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच सकता है। इंग्लैंड को फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को टेस्ट सीरीज में 3-0, 3-1, या 4-0 से हराना होगा।

शाकिब की वापसी से लाभ होगा : मोमिनुल

चटगांव, (एजेंसी)। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान मोमिनुल हक ने कहा है कि कि अनुभवी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन की वापसी से वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला में उनकी टीम को लाभ मिलेगा। शाकिब इस मैच में उतरने के साथ ही सितंबर 2019 के बाद पहली बार टेस्ट मैच खेलेंगे। शाकिब पर लगा आईसीसी प्रतिबंध हाल ही में समाप्त हुआ है। मोमिनुल ने कहा, ऐसे खिलाड़ी किसी भी टीम के लिए बेशकीमती हैं। वह टीम में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से योगदान दे सकते हैं लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि उनके आने से टीम का संयोजन बेहतर होता है। शाकिब का टेस्ट में बल्ले से 39.40 और गेंद से 31.12 का औसत है। वह 25 जनवरी को खेले गये एकदिवसीय श्रृंखला के तीसरे मैच के दौरान चोटिल हो गये थे लेकिन कोच रसेल डोमिंगो को उम्मीद है कि वह पहले टेस्ट में खेलेंगे।

डोमिंगो ने कहा, किसी भी प्रारूप में शाकिब की जगह किसी और को चुनना काफी मुश्किल काम है। हम इस बात को लेकर आश्वस्त है कि वह पहले टेस्ट में खेलेंगे। उन्होंने बिना किसी परेशानी के बल्लेबाजी और गेंदबाजी अभ्यास किया है। शाकिब के आने से मजबूत हुई बांग्लादेश को घरेलू माहौल में खेलने का फायदा मिलेगा। वैसे भी वेस्टइंडीज की टीम के कई अनुभव खिलाड़ी कोरोना वायरस के डर से इस दौरे पर नहीं आये है जिसमें कप्तान जेसन होल्डर, शाई होप और शिमरॉन हेटमायर शामिल हैं। ऐसे में टीम पहले ही कमजोर है। बंग्लादेश की टीम लगभग एक साल बाद पहला टेस्ट खेलेगी और वेस्टइंडीज के कोच फिल सिमंस को उम्मीद है कि उनकी टीम इसका फायदा उठाएगी। वेस्टइंडीज ने इस दौरान पांच टेस्ट खेले है लेकिन उसे चार में हार का सामना करना पड़ा है। सिमंस ने कहा, मुझे लगता है कि लंबे समय के बाद टेस्ट खेलने के कारण उनकी टीम थोड़ी असहज होगी।

पहले टेस्ट में जगह के लिए इशांत और सिराज में होगा मुकाबला

चेन्नई, (एजेंसी)। इंग्लैंड के खिलाफ शुक्रवार से यहां शुरू होने वाले पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया में स्थान के लिए अनुभवी तेज गेंदबाज इशांत शर्मा और युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज में कड़ा मुकाबला होगा। सिराज ने ऑस्ट्रेलिया दौरे में शानदार प्रदर्शन कर इस मैच के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। भारतीय टीम यहां के पारंपरिक विकेट को देखते हुए पांच से नौ फरवरी तक होने वाले पहले टेस्ट में दो तेज गेंदबाजों और तीन स्पिनरों के साथ उतर सकती है। इस विकेट से स्पिनरों को मदद मिलेगी जैसा कि हमेशा होता है। सभी की नजरें मुख्य कोच रवि शास्त्री, गेंदबाजी कोच भरत अरूण और कप्तान विराट कोहली की तिकड़ी पर टिकी होगी कि वह तेज गेंदबाजी आक्रमण की शुरूआत के लिए जसप्रीत बुमराह के जोड़ीदार के इशांत और सिराज में से किसे शामिल करते हैं।

इशांत ने पिछले लगभग एक साल से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है जबकि सिराज आस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार फॉर्म में थे जहां उन्होंने ब्रिसबेन में एक पारी में पांच विकेट सहित तीन टेस्ट में कुल 13 विकेट लिए हैं, ऐसे में उन्हें जगह मिलने की ज्यादा उम्मीदें हैं। इशांत ने हाल में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की है जहां उन्होंने चार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैचों में कुल 14.1 ओवर गेंदबाजी की। उम्मीद है कि गेंदबाजी कोच अरूण अगले दो दिन में इशांत और सिराज को लेकर फैसला करेंगे। वहीं फॉर्म में चल रहे वाशिंगटन सुंदर और बायें हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल में से एक को रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव का साथ देने के लिए शामिल किया जा सकता है। सुंदर ने ब्रिसबेन में पदार्पण करते हुए अर्धशतक जड़ा और चार विकेट लिए थे। वहीं अक्षर गेंदबाजी के साथ ही बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या भी अपना पृथकवास पूरा कर आज टीम से जुड़ जाएंगे।

एससी ईस्ट बंगाल के कोच फाउलर पर प्रतिबंध, जुर्माना

कोलकाता (ईएएमएस)। इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) फुटबॉल टूर्नामेंट में कोच रॉबी फाउलर पर प्रतिबंध के साथ ही जुमार्ना भी लग सकता है। फाउलर पर एफसी गोवा के खिलाफ मैच के बाद रैफरी के खिलाफ कथित तौर पर नस्लीय टिप्पणी के आरोप हैं। इस मामले के लिए उनपर कम से कम पांच मैचों का प्रतिबंध लगाये जाने के साथ ही छह लाख रुपये जुमार्ना लग सकता है। मडगांव में 29 जनवरी को हुए एक मैच में एफसी गोवा के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ के बाद फाउलर ने कहा था कि रैफरी इंग्लिश विरोधी या ईस्ट बंगाल विरोधी था। वहीं इस मामले में आईएसएल के एक अधिकारी ने कहा कि मैच आयुक्त ने घटना के प्रति कड़ा रुख अपनाया है और मामला अनुशासनात्मक समिति के पास भेजा है। उन्होंने कहा कि अगर कोच दोषी पाए गए तो उन्हें कम से कम पांच मैचों के प्रतिबंध और छह लाख रुपये जुमार्ने का सामना करना होगा।

ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका दौरा स्थगित किया

सिडनी, (एजेंसी)। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने अपना दक्षिण अफ्रीका दौरा स्थगित कर दिया है। इससे ऑस्ट्रेलिया का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का रास्ता अब कठिन हो गया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के 332 अंक हैं और 69.2 प्रतिशत अंकों के साथ वो तीसरे नंबर पर है।

फाइनल में पहुंचने के लिए उसे दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जीत दर्ज करना जरूरी था लेकिन अब ये दौरा ही स्थगित हो गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया से अपने घर पर 1-2 से सीरीज गंवा दी जिसका उसे अब बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया को दक्षिण अफ्रीका दौरे पर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी थी। इस सीरीज में जीत से उसकी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद बन सकती थी, लेकिन अब ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। वहीं न्यूजीलैंड को लाभ मिला है और वह आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई है।

ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने सीए के इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। उसने सीए के सीईओ निक हॉकली का आधिकारिक बयान ट्वीट किया है जिसके अनुसार अब ऑस्ट्रेलियाई टीम दक्षिण अफ्रीका दौरे पर नहीं जाएगी। इससे साफ है कि पहले नंबर पर चल रही भारत और दूसरे स्थान पर बरकरार न्यूजीलैंड की टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगी।

तेज गेंदबाज डिंडा ने संन्यास लिया

कोलकाता, (एजेंसी)। बंगाल के तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने क्रिकेट के सभी प्रारुपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। डिंडा ने अपने डेढ़ दशक लंबे करियर के दौरान घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 116 फर्स्ट क्लास मैचों में 420 विकेट हासिल किए हैं।

36 साल के डिंडा ने भारत की ओर से 13 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के साथ ही नौ टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इसमें इस गेंदबाज के नाम एकदिवसीय में 12 और टी-20 में 17 विकेट हैं। डिंडा ने गोवा की ओर से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तीन मुकाबले खेले पर इस दौरान उन्हें अहसास हुआ कि अब वह आगे अधिक नहीं खेल पायेंगे। डिंडा ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में भी दिल्ली डेयरडेविल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर), पुणे वॉरियर्स इंडिया, राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेला था। इस तेज गेंदबाज ने 78 आईपीएल मैचों में 21.97 के स्ट्राइक रेट से 69 विकेट लिए थे।

वह उत्पल चटर्जी के बाद बंगाल के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं। डिंडा ने कहा, मैं क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले रहा हूं। मैंने बीसीसीआई और गोवा क्रिकेट संघ को इस संबंध में इमेल भेज दिया है। डिंडा ने बीसीसीआई के अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को धन्यवाद दिया। गांगुली ने ही साल 2005-06 सत्र में इस तेज गेंदबाज को डेब्यू का अवसर दिया था। बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अविषेक डालमिया, सचिव स्नेहाशीष गांगुली और संयुक्त सचिव देवव्रत दास ने डिंडा को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें चांदी की पट्टिका और फूलों का गुलदस्ता दे कर सम्मानित किया।

मिलान में युवेंटस के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टीयानो रोनाल्डो इटली कप फुटबॉल के सेमीफाइनल मैच में खेलते हुए।

आईपीएल नीलामी में इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें

मुम्बई, (एजेंसी)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 14 वें सत्र के लिए इसी माह की 18 तारीख को चेन्नई में होने वाली नीलामी में इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें। इस सत्र के नीलामी से पहले टीमों ने कई खिलाड़ियों को रिलीज किया। जिनमें अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल भी शामिल हैं। फ्रेंचाइजी टीमों ने कुल 139 खिलाड़ियों को रिटेन रखा, जबकि 57 खिलाड़ियों को रिलीज किया।

स्टीव स्मिथ- ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्मिथ को राजस्थान रॉयल्स ने रिलीज कर दिया था। स्मिथ 2018 आईपीएल सत्र से अब तक टीम के कप्तान भी रहे थे हालांकि आरआर पिछले साल अंक तालिका में सबसे नीचे रहा था। साथ ही, स्मिथ ने भी बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था. फिर भी, इस सत्र के लिए टीमों की निगाहें स्मिथ को खरीदने पर होंगी।

उमेश यादव- पिछले कुछ आईपीएल से यह भारतीय गेंदबाज अपनी छाप नहीं छोड़ पाया है। उमेश आरसीबी के साथ पिछले तीन सत्र से जुड़े थे। वह खिताब जीतने वाली कोलकाता नाइटराइडर्स टीम का हिस्सा रहे हैं। उमेश ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लय में दिखे थे, लेकिन चोट के कारण उन्हें दौरा बीच में ही छोड़ना पड़ा था. मैच जिताने की काबिलियत के चलते कई टीमें इन पर बोली लगा सकती हैं।

शिवम दुबे- यह ऑलराउंडर बल्ले और गेंद दोनों के साथ अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। साथ ही वह अच्छे फील्डर माने जाते हैं पर शिवम पिछले सत्र में आरसीबी के लिए संघर्ष करते दिखाई दिए थे। फिर भी गेंद और बल्ले से मैच जिताने की क्षमता के कारण टीमों की नजरें उन पर रहेंगी।

ग्लेन मैक्सवेल- मैक्सवेल आईपीएल में अब तक अपने नाम के अनुरुप प्रदर्शन नहीं कर पाये हैं। आम तौर पर वह ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए बिग बैश लीग में बढ़िया प्रदर्शन करते आये हैं। किंग्स इलेवन पंजाब ने उन्हें इस सत्र के लिए रिलीज कर दिया था। मैक्सवेल की आक्रामक बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग उन्हें सबसे अलग बनाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन-सी टीम मैक्सवेल को खरीदती है।

कृष्णप्पा गौतम- गौतम ने घरेलू क्रिकेट में बढ़िया प्रदर्शन किया है। गौतम पिछले सत्र में किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से खेले थे हालांकि, उन्हें पंजाब ने उन्हें सिर्फ दो मैचों में मौका दिया था. गौतम स्पिन गेंदबाज के साथ ही निचले क्रम के उपयोगी बल्लेबाज भी हैं। इस कारण टीमें गौतम को खरीदने के लिए बोली लगा सकती है।

क्रिस मॉरिस- दक्षिण अफ्रीका के आलराउंडर मॉरिस पिछले सीजन में आरसीबी के लिए गेंद से बेहतर प्रदर्शन किया था। पिछले सत्र में आरसीबी ने मॉरिस को 10 करोड़ की बड़ी कीमत में खरीदा था। शायद इसीलिए आरसीबी ने मॉरिस को रिलीज कर दिया। मॉरिस तेज गेंदबाजी के साथ ही आक्रामक बल्लेबाजी करने में भी सक्षम हैं। इसलिए चेन्नई, पंजाब जैसी टीमें उनको खरीदने का प्रयास करेंगी।

नाथन कूल्टर नाइल- ऑस्ट्रेलिया के इस गेंदबाज ने पिछले सत्र में मुंबई इंडियंस के लिए 7 मैच खेले थे। कूल्टर नाइल ने फाइनल में भी बढ़िया गेंदबाजी की थी। वह भी टीमों के लिए बेहतर विकल्प बन सकते हैं।

जेम्स पेटिंसन- मुम्बई इंडियंस ने पेटिंसन को रिलीज कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। पेटिंसन ने पिछली बार 10 मैचों में 11 विकेट लेकर मुम्बई इंडियंस की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी। पेटिंसन को इस सत्र में फिर से अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है।